

जल प्रहरी

2025

Souvenir
स्मारिका

Supported by



INCREDIBLE ENGINEERING INFRASTRUCTURE FOR FUTURE

Afcons Infrastructure Ltd is flagship infrastructure engineering and construction company of the Shapoorji Pallonji Group



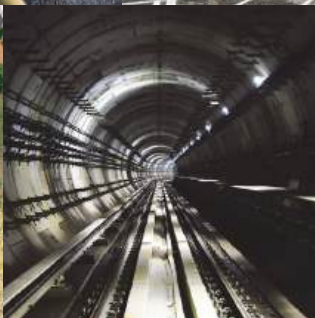
Legacy of over six decades

Strong track record of
executing complex, challenging
and unique projects

Presence/delivered projects in
25 countries across South Asia,
Africa, Middle East, and CIS

Ranked in Top 140 international
Contractors globally; 14th in
Marine & Ports; 12th in Bridges
(ENR Survey 2024)

Won MAKE/MIKE award for nine
consecutive years



Afcons Infrastructure Limited

Regd. Office: Afcons House, 16, Shah Industrial Estate,
Veera Desai Road, Azad Nagar, Andheri(W),
Mumbai - 400 053, India, Tel.: +91-22-6719 1000
www.afcons.com | CIN No.: L45200MH1976PLC019335

AFCONS

Table Of Contents



Glimpses	10
MANAGEMENT TEAM	18
आकांक्षा कोंडे	20
BIBHU CHOWDHURY	22
अनिरुद्ध जयकुमार तोडकर	24
भीला पाटिल	26
साकेत	28
ORGANIZING TEAM	30
Dhanlakshmi Ramachandra	32
धवल पांड्या	34
बिंदिया सक्सेना	36
डॉ. नीलकुमार सुमंतराय देसाई	38
प्रो.डॉ. एच.एम. पाटिल	40
एकनाथ मोतीलाल माळतकर	42
तरूण वैद्य	44
हिमांशु नागपाल	46
कामिनी कुमारी	48
किशोर जायसवाल	50
मधुकर स्वयंभू, चंद्रशेखर	52
आकांक्षा सैमुअल	54
नेहपाल सिंह	56
नीरज त्रिवेदी	58
निर्मल यादव	60
पुनीत खन्ना, हिना खन्ना	62
राजेश कुमार शुक्ला	64
रामेश्वर लाल मीणा	66
Rizwan Basha Shaik	68
Sabyesachi Bharti	70

भोज कुमार साहू	72
संजय राणा	74
सोनाक्षी श्री	76
सोनू गहलोत	78
गौतम कुमार सिंह	80
विनोद खाती	82
डॉ. बृजकिशोर गुप्ता	84
पद्मभूषण अनिल प्रकाश जोशी	86
छोटी नदियों को पुनर्जीवित करना	
सबसे पहली जरूरत है	88



Message

अनिल सिंह सागर, वरिष्ठ पत्रकार



**जल आत्मनिर्भर
भारत का लक्ष्य
हासिल करने के
लिए प्रत्येक जल
स्रोत पर
व्यवहारिकता से हों
फैसले**

जल राज्य संबंधित विषय होने के चलते जल संसाधनों से संबंधित पहलुओं, जिसमें उनके संरक्षण भी शामिल है, का अध्ययन, योजना, मूल्यांकन, वित्तपोषण और क्रियान्वयन राज्य सरकारें अपने संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार स्वयं करती हैं। केंद्र सरकार विभिन्न तकनीकी, वित्तीय और नीति-स्तर पर राज्यों के प्रयासों में पूरक का काम करती है।

जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा लागू किए गए जल शक्ति अभियान, कैच द रेन (जेएसए-सीटीआर) अभियान के तहत, कृत्रिम रिचार्ज संरचनाओं के प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी आदि के लिए लाभ लिया जा सकता है। जेएसए-सीटीआर में जल संरक्षण की वैज्ञानिक योजनाएं तैयार करने के लिए जल निकायों की गणना, जियो-टैगिंग और उनका सूचीकरण करना है। जिला कलेक्टरों और मजिस्ट्रेटों से पुराने राजस्व रिकॉर्ड, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी (एनआरएसए) से रिमोट सेंसिंग डेटा और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मैपिंग तकनीक का उपयोग करके जल निकायों की गणना करने, सीमाओं को चिह्नित करने, संरचनाओं को जियो-टैग करने और राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र (एनडब्ल्यूआईसी) तथा राज्य जल संसाधन सूचना प्रणालियों से डेटा को एकीकृत करने का अनुरोध किया जा रहा है। इससे डेटा-संचालित वैज्ञानिक संरक्षण योजनाओं के विकास को सक्षम बनाया जा सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार

जेएसए-सीटीआर पोर्टल पर उपलब्ध, 639 जिलों ने जिला योजनाएं तैयार की हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने इंडिया-ग्राउंडवाटर रिसोर्स एस्टिमेशन सिस्टम (इन-जीआईएस) विकसित किया है, जो एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है और पूरे देश में भूजल संसाधन मूल्यांकन के लिए एक मानकीकृत मंच प्रदान करता है, जिससे केंद्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा इसका लगातार कार्यान्वयन संभव हो पाता है। सीजीडब्ल्यूबी, 5,260 डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर्स (डीडब्ल्यूएलआर) के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से रियल टाइम में भूजल स्तर की निगरानी करता है, जो टेलीमेट्री सिस्टम से लैस हैं और उनका डेटा इसके ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है। एक्वीफायर की मैपिंग, रिचार्ज क्षेत्रों की पहचान करने, स्रोत की स्थिरता का आकलन करने और स्थानिक भूजल विश्लेषण करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) और रिमोट सेंसिंग जैसे उन्नत उपकरणों को एकीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, बड़े पैमाने पर भूजल भंडारण मूल्यांकन के लिए ग्रेस (ग्रेविटी रिवकवरी एंड क्लाइमेट एक्सीपेरिमेंट) जैसे प्लेटफार्मों से उपग्रह डेटा का लाभ उठाया जाता है, जबकि एनआईएसएआर (नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्वर रॉडार) जैसे मिशनों के साथ सहयोग का उद्देश्य मैक्रो स्तर पर भूजल परिवर्तनों का पता लगाने की क्षमता को बढ़ाना है।



GS SISTANI
(Justice, Retd. Delhi High Court)



Mr. YUGAL JOSHI
Lead-Communication &
NER, Niti Ayog



Mr. NITIN WAGMORE
(IRS Commissnor)
Income Tax, Pune



Mr. SH. KK KHANDELWAL
(Retd., IAS)



Mr. MANOJ KUMAR
(ex. IAS, VC Singhania
University)



Mr. MCT Pareva
(CPWD, ADG, Retd.)



Mrs. NEETU NAVGEET
Folk Singer Brand Ambessdor
of Election Commision Bihar



Mr. Ajay Kaushik
(Delhi Tourism)



Mr. MOHAN NAGAR
(Vice President)
MP People's Campaign
Council
(Planning, Economics and
Statistics Department,
Government of MP)



छठा संस्करण जल



श्री सीआर पाटिल
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री



श्री डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री



श्रीमती रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री, दिल्ली



श्री मनोज तिवारी
सांसद, उत्तरी पूर्वी दिल्ली



श्री रामदास आठवले
राज्य मंत्री, समाज कल्याण, केंद्र सरकार



श्री प्रवेश साहिब सिंह
जल संसाधन मंत्री, दिल्ली सरकार

श्री आशीष सूद
शिक्षा मंत्री, दिल्ली सरकार

श्री अशोक रावत
सांसद, मिसश्रिख

Supported by



RSVP : Anil Singh, Manoj Pandey, Sanket Chaturvedi, Ajay Gupta

सुजलम भारत की दिशा में एक पहल...

प्रहरी

2025



श्री राजभूषण चौधरी
राज्य मंत्री, जल शक्ति, केंद्र सरकार



श्री पूज्य स्वामी चिदानन्द सरस्वती
परमार्थ निकेतन



श्री विजेन्द्र गुप्ता
विधानसभा अध्यक्ष, दिल्ली



श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
पर्यावरण मंत्री, दिल्ली सरकार



श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी
सांसद, दक्षिणी दिल्ली



श्री अरूण सिंह
सांसद, राज्यसभा

श्रीमती धर्मशिला गुप्ता
सांसद, जल संसाधन समिति सदस्य

श्री सतीश उपाध्याय
विधायक, दिल्ली

श्री गोपाल आर्य
पर्यावरण विधि प्रमुख, आरएसएस



अमरउजाला



THE BHARAT SCOUTS AND GUIDES
Creating - Better India
Since 1909



9811390602, 9345193248

Date : 11 December 2025

Venue : New Maharashtra Sadan, KG Marg, New Delhi-110001

Glimpses-2019









Glimpses-2022 from Jal Prahari







Glimpses-2023 from Jal Prahari





Glimpses-2024 from Jal Prahari







MANAGEMENT TEAM



Mrs. Mandeep Kour
(Principal)



Simarjeet Singh



Aditya Jha



Rudra Gola



Mohd Arshan



Kartik Bhati



Devanshi Gautam



Annya Bharti



Nandika



Rajvir Singh



Daarun Liloithia



Gurvansh Singh



Bhawana Kapoor



दिल्ली मेट्रो

शहरी परिवहन के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत



दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन – भारत सरकार और दिल्ली सरकार का एक संयुक्त उपक्रम – वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में से एक का संचालन कर रही है, जो राजधानी दिल्ली और इसके उपनगरों को जोड़ता है।

डीएमआरसी के फेज़-IV विस्तार योजना के अंतर्गत लगभग 111 किलोमीटर अतिरिक्त नेटवर्क का निर्माण भी किया जा रहा है।



मुख्य विशेषताएँ:

- ⊗ 1995 में स्थापित, दिल्ली मेट्रो अब अपने 31वें वर्ष में देश की सेवा कर रही है।
- ⊗ यह विश्व के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में से एक है, जिसमें 394* किमी लंबा परिचालन नेटवर्क और 289 स्टेशन शामिल हैं।
- ⊗ प्रतिदिन औसतन 65 लाख से अधिक यात्राएँ की जाती हैं।
- ⊗ 29 इंटरचेंज स्टेशनों के माध्यम से सभी कॉरिडोर पर सहज और सुगम यात्रा की सुविधा।
- ⊗ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने वाली विश्व की पहली मेट्रो रेल और रेल आधारित प्रणाली।
- ⊗ डीएमआरसी की कुल दैनिक ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 35% नवीकरणीय ऊर्जा (सौर ऊर्जा व अपशिष्ट से उत्पादित ऊर्जा) द्वारा पूरा किया जाता है।

*रेपिड मेट्रो कोरिडोर, गुरुग्राम एवं नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्वा लाइन का परिचालन डीएमआरसी के सुपरविजन में किया जाता है।

* दिसंबर 2025



दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
DELHI METRO RAIL CORPORATION LTD.

आकांक्षा कोड़े

आईएस, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, हरिद्वार, उत्तराखंड

हरिद्वार से जल संवर्धन, समृद्ध, अतिक्रमण मुक्त सरोवर देते हैं संदेश



मां, गंगा हरिद्वार से भारत के दूसरे राज्यों की ओर बढ़ती हैं और समृद्धि फिर हरिद्वार में जल संरक्षण, संवर्धन की क्या आवश्यकता! वर्षा जल संरक्षण, तालाबों एवं जल स्रोतों में पुनर्भरण की यह नई तस्वीर, है एक संदेश

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद हरिद्वार में एक बड़ा क्षेत्रफल वनस्पतियों से घिरा हुआ है, जिसमें राजाजी टाइगर रिजर्व भी सम्मिलित है। साथ ही जनपद का कुछ क्षेत्र औद्योगिक भी है, हरिद्वार में जल का मुख्य स्रोत गंगा नदी है। आधुनिकता एवं विकास के कारण आज समस्त भारत में विभिन्न स्थानों पर पानी का संकट निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसके दृष्टिगत भारत एवं राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने स्तर पर जल संरक्षण हेतु विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं।

भारत सरकार द्वारा जल शक्ति अभियान के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में जिला प्रशासन के नेतृत्व में विभिन्न विभागों द्वारा वर्षा के जल संरक्षण हेतु राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना SARRA के अंतर्गत वर्षा के जल को संगृहीत करने के लिए तालाब, जल स्रोत बन रहे हैं। वृत्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा योजना एवं अन्य विभागों द्वारा लगभग 3435.31 लाख लीटर जल संग्रहित करने के लिए तालाबों व अन्य, जल पुनर्भरण स्रोतों का निर्माण किया गया है। इससे मनरेगा में 1,26,393 लाभार्थियों को लाभ भी मिला।

मनरेगा द्वारा जल पुनर्भरण की संरचनाओं के निर्माण में गांवों में आगनबाड़ी, सरकारी भवन, प्राथमिक विद्यालयों आदि को भी सम्मिलित किया

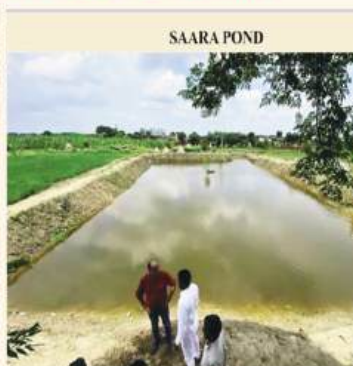
गया है। मत्स्य विभाग ने वर्ष 24-25 में तालाब बनाए जहां जल संग्रहण क्षमता 6519.00 लाख लीटर पहुंच गई। कुछ तालाबों को आर्थिक रूप से अशक्त ग्रामीणों को पट्टे पर 29 वर्ष हेतु आवंटित किये गए जहां वे मत्स्य पालन कर अपनी आजीविका को बेहतर बना रहे हैं। जिला प्रशासन ने 28 तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करा कर उनका पुनर्भरण करवाया व कई अन्य अतिक्रमण किए तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की कार्यवाही चल रही है।

निति आयोग, भारत सरकार द्वारा कुल 50 तालाबों को जनपद हरिद्वार के ब्लाक बहादुराबाद में अंकित किया गया था, जिस पर जिला प्रशासन

के निरन्तर प्रयासों द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से पूर्ण करा दिया गया है। जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत 96 बंद बोरवेल को चिन्हित कर वर्षा जल को भू-जल पुनर्भरण हेतु रिचार्ज शाफ्ट में परिवर्तित किया गया है, जिससे रिचार्ज शाफ्ट के निर्माण में वित्तीय एवं समय की बचत भी हुई है, जिला प्रशासन द्वारा उक्त आंकड़ों को प्रति वर्ष बेहतर करने हेतु निरन्तर प्रयासरत है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत मुख्यतः वन विभाग व अन्य विभागों द्वारा कुल 980.667 हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण कर वनस्पति को बढ़ावा देने का प्रयास भी जिला प्रशासन के नेतृत्व में निरन्तर किया जा रहा है।



सारा अन्तर्गत किये गये कार्यों के फोटोग्राफ



Meghraj Ke yahan Recharge Pit, G.P- Banganga, Block- Bahadrabad



वन विभाग द्वारा निर्मित चालखाल



BIBHU CHOWDHURY(Secretary, Arindam Choudhury (CEO),
Chotanagpur Craft Development Society (CCDS))

Conservation of Natural Resources, Promotion of people's Prganization like Self-help Group

Chotanagpur Craft Development Society (CCDS) is committed to improving the lives of India's underprivileged, with a special focus on women, children, and youth. CCDS does this through high-impact interventions in livelihoods and environment because poverty is multidimensional. CCD S's unique value proposition is its broad engagement between communities, civil society, and expertise, thereby building a lasting bridge between the grass roots and planning. With India operations headquartered in Ranchi, Jharkhand, CCDS has impacted about 2.51 million lives across the Nation. CCDS is widening livelihood options, as one of the key adopted strategies, both farm and non-farm sectors for reducing poverty in the remote underdeveloped tribal pockets of Jharkhand and Chattisgarh Popularization of sustainable agriculture practices,

conservation of natural resources, promotion of people's organization like Self-help group (SHG), farmers group, primary producers groups and their federations, facilitation of people's access to micro-finance and government schemes, enhancement of market linkages and provision of skill-building support for promotion of off and non-farm micro enterprise/ social

enterprise are some of the key elements in this pursuit. Focusing on water conservation, watershed management, climate action and environment restoration, CCDS has been working dedicatedly in the grassroots level, with NABARD, State Government of Jharkhand and HINDALCO (Aditya Birla Group company), both in Jharkhand and Chattisgarh.





अनिरुद्ध जयकुमार तोड़कर

मैप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, विश्रान्तवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र



देश की बड़ी आबादी भूजल पर ही निर्भर है

ग्लोबल वार्मिंग से कुदरती पानी के सोर्स पर बुरा असर पड़ रहा है, जिससे घटते ग्राउंडवॉटर सोर्स पर निर्भरता बढ़ रही है। पानी की इस मुश्किल से निपटने के लिए आखिर क्या विकल्प हैं। यह समझ विकसित कर पुणे में बनाया दिया इतिहास

भारत में, सरफेस वॉटर बहुत ज्यादा प्रदूषित है, जिसमें बिना ट्रीट किया हुआ घरेलू सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट वगैरह आ जाता है। चूंकि देश की बड़ी आबादी भूजल पर ही निर्भर है और उसके लिए यही प्रमुख स्रोत है तो इसे सुरक्षित रखना भी आवश्यक है।

ऐसे में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सूखते हुए एक्विफर को रिचार्ज करने के सबसे जाने-माने तरीकों में से एक है। इससे तुरंत नतीजे और फायदे मिलते हैं। अनिरुद्ध जयकुमार तोड़कर व उनकी मैप्स इंडिया की टीम के पास कई सूखे से जूझ रहे गांवों में रूफटॉप रेनवॉटर हार्वेस्टिंग टेक्नीक को लागू करने का अनुभव गांव-गांव में लोगों के काम आया।

यह पाया गया है कि जिन लोगों ने पहले के सालों में रूफटॉप रेनवॉटर हार्वेस्टिंग का काम किया था, उन्हें पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं हुई और उनके पास अपनी दूसरी घरेलू जरूरतों के लिए भी पानी था। अनिरुद्ध पिछले कुछ सालों से, जल आत्मनिर्भर अभियान के तहत महाराष्ट्र के पानी की कमी वाले मराठवाड़ा इलाके में काम कर रहे हैं। वर्ष 2021 में विभिन्न वित्तीय संस्थानों की मदद से अंबेगांव तालुका के चार गांवों में रूफटॉप रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

लगाए, जिससे वे चार गांव टैंकर के पानी से मुक्त हो गए।

इस सफलता के साथ, महाराष्ट्र के बीड जिले के पानी की कमी वाले 100 गांवों और धाराशिव जिले के कलमाब तालुका के 31 गांवों में रूफटॉप रेनवॉटर प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए फाइनेंशियल मदद मिली और फिरएक्सपर्ट टीम ने अनिरुद्ध तोड़कर के नेतृत्व में ये प्रोजेक्ट सात महीने के रिकॉर्ड समय में सफलतापूर्वक पूरा किए। इस प्रोजेक्ट में 5887 से ज्यादा स्ट्रक्चर शामिल थे, जिसमें अलग-अलग घर, स्कूल, धार्मिक इमारतें और सरकारी इमारतें शामिल थीं।

इसमें 50 लाख वर्गफीट छत का एरिया

शामिल था। इससे हर साल 3916 बोरवेल और 267 खुले कुओं से ग्राउंड टेबल रिचार्ज के लिए 30 करोड़ लीटर बारिश का पानी इकट्ठा हो सकता है। इस वजह से, पांच लाख गांव वालों को टैंकर के पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह भारत का सबसे बड़ा रूफटॉप रेनवॉटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट माना जाता है। बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग से कुदरती पानी के सोर्स पर बुरा असर पड़ रहा है, जिससे घटते ग्राउंडवॉटर सोर्स पर निर्भरता बढ़ रही है। पानी की इस मुश्किल से निपटने के लिए ग्राउंडवॉटर रिचार्ज ही एकमात्र तरीका है। हमारी अनुभवी टीम इस देश के मकसद के लिए समाधान देने को तैयार है।





भीला पाटिल

चिंचवाड, महाराष्ट्र



पानी सभी तरह के जीवन के लिए जरूरी एक बुनियादी चीज

खेतिहर मजदूर परिवार का इंजीनियर बेटा, जिसने पानी के लिए पाइप से बनाया जल आत्मनिर्भरता का एक पाठ

अगर आपके पास पानी है, तो आपके पास सब कुछ है। पानी के बिना कुछ भी नहीं है। पानी सभी तरह के जीवन के लिए जरूरी एक बुनियादी चीज है, जो खेती, इंडस्ट्री और रोजाना के इंसानी कामों में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलग-अलग इस्तेमाल में से, सिंचाई सबसे जरूरी इस्तेमाल में से एक है, जो खाने की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पक्का करती है। खेती में, फसल की ग्रोथ के लिए पानी जरूरी है, क्योंकि यह मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स को सोखने में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस को बढ़ावा देता है और पौधों का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। सही और समय पर सिंचाई से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और फसल की पैदावार बढ़ती है, जिससे यह सस्टेनेबल खेती का एक अहम हिस्सा बन जाता है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और बढ़ते टेम्परेचर के साथ, आज भारत के बड़े शहरों में हर गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है। ऐसे समय में भीला सोनू पाटिल जैसे लोगों का काम बहुत जरूरी और जान बचाने वाला हो जाता है। एक सफल इंजीनियर होने और पेशेवर जिंदगी के बीच उन्होंने पानी बचाने और उसे फिर से जिंदा करने के लिए समय और उर्जा लगाई। उन्होंने 10000 से ज्यादा लोगों को पानी बचाने के तरीके बताने के लिए 25 से ज्यादा वेबिनार और संबोधन, सेमिनार किए हैं।

उन्होंने जल संवाद यात्रा नाम का एक वॉटर मार्च निकाला, जो सिर्फ गिरते पानी के लेवल के बारे में जागरूकता लाने और लोगों और सरकार से कार्रवाई करने की अपील करने के लिए सात दिनों में नॉर्थ महाराष्ट्र के अलग-अलग जिलों से होकर 1500 किमी से ज्यादा सफर तय किया। उन्होंने न सिर्फ पानी बचाने के लिए, बल्कि स्कूल सप्लाई के लिए फंडिंग, बाढ़ राहत के साधन देने और महामारी के दौरान भी हाथ बढ़ाया। फार्म इरिगेशन एमिटर्स, स्प्रिंकल्स, पाइप्स और दूसरे इक्विपमेंट्स के प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट में स्पेशलिस्ट/दो दशकों का वर्किंग एक्सपीरियंस। एग्रीकल्चर में वॉटर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, खासकर जरूरी आउटपुट की मात्रा को कंट्रोल करने और वेस्टेज

को कम करने में सही पाइप सहायक होते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग से ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकल्स और नोजल्स में असेंबल किए गए पाटर्स बनते हैं। भीला पाटिल को इंडियन प्लास्टिक टूलिंग इंजीनियरिंग सेक्टर में 38 साल का अनुभव है और उन्होंने एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोडक्ट्स, पाइप्स फिटिंग, सॉइल वेस्ट रेनवाटर पाइप्स फिटिंग, हाउसहोल्ड, लो और हाई टेक्नोलॉजी ऑटोमोटिव पाटर्स व लैप्स के लिए इंजिनरिंग प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग टूलिंग और ड्रिप पाइप, मल्टी-कलर लेटरल ट्यूब्स, एमिटर्स, स्प्रिंकल्स, विंडो प्रोफाइल एक्सट्रूडर डाइज के डिजाइन और डेवलपमेंट का अनुभव है जो जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।





Environment & Engineering

Environmental & Water Engineering Management Journey

- Water Culture
- Water Literacy
- Water Harvesting
- Water Irrigation
- Water Security



- जल संस्कृती
- जल साक्षरता
- जल संचय
- जल सिंचन
- जल सुरक्षितता

- ❖ Apart from Engineering professional work also working as Secretary, Jal Parishad, North Maharashtra Khandesh Vikas Mandal for Environment, Water Engineering Management and River Rejuvenation for Clean River activities, village side water shade development guidance and support.



साकेत

डिप्टी चीफ इंजीनियर, वाराणसी रेल इंजन कारखाना, वाराणसी

लोहे में लगाकर दिल पटरी पर चलाते हैं, प्रकृति से लेकर प्रकृति को लौटाते हैं



जल और पर्यावरण संरक्षण के लिए डीप रिचार्ज बोरेवेल और सोक पिट बनाए। तालाबों का निर्माण किया गया और एसटीपी और डब्ल्यूआरपी द्वारा उपचारित जल का पुनः उपयोग किया गया। जैव उर्वरक का उत्पादन, वृक्षारोपण भी कारखाने की शान है

बीएलडब्ल्यू कारखाना परिसर में डीप रिचार्ज बोरेवेल और सोक पिट के माध्यम से जल संरक्षण किया गया जहां डीप रिचार्ज बोरेवेल और सोक पिट का निर्माण करवाया; ऐसे 71 डीप रिचार्ज बोरेवेल और 426 सोक पिट के माध्यम से भूजल रिचार्ज किया जा रहा है। इसमें से 31 का निर्माण चालू वर्ष में किया गया है और 9 बोरेवेल पर कार्य प्रगति पर है। इन डीप रिचार्ज बोरेवेल के माध्यम से सालाना लगभग 3,38,549 घन मीटर पानी रिचार्ज किया जा रहा है। रिचार्ज किए गए पानी का कुल मूल्य 4,40,100 रूपए होगा। ग्राउंड वॉटर को रिचार्ज करने के लिए 147 सोक पिट्स का काम चल रहा है। बीएलडब्ल्यू में 100 डीप रिचार्ज कुओं का कंस्ट्रक्शन 2025-26 के प्रस्ताव पर काम चल रहा है। डीप रिचार्ज वेल-41 में से 9 डीप रिचार्ज कुओं का काम चल रहा है। अब तक 71 डीप रिचार्ज वेल पूरे हो चुके हैं। एसटीपी व वॉटर रीसाइक्लिंग प्लांट के ट्रीटेड पानी का दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है और यहां 1989 से एक 12 एमएलडी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और एक 3 एमएलडी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट चला रहा है। बदले हुए पैरामीटर्स (परमिसिबल नॉम्स) को पूरा करने के लिए 12 12 एमएलडी के प्लांट अपग्रेड करने की योजना पर काम चल रहा है और बीएलडब्ल्यू सभी ट्रीट किए गए सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट वॉटर को

ग्राउंड वॉटर रिचार्जिंग और हॉर्टिकल्चर जैसे पर्यावरण के लिए फायदेमंद कामों में दोबारा इस्तेमाल कर रहा है। लगभग 3.5 एमएलडी पानी की इस रीसाइक्लिंग से ताजे पानी की जरूरत बचती है और इसका इस्तेमाल लॉन की सिंचाई और पानी की जगहों को भरने में किया जाता है। हर साल रीसायकल किए गए पानी की कुल कीमत 16 लाख रूपए से अधिक होती है।

ट्रीट किए गए पानी को 2 वॉटर रीसाइक्लिंग प्लांट के जरिए आगे ट्रीट किया जाता है। इस आगे ट्रीट किए गए पानी को सूर्य सरोवर और गोल्फ कोर्स के तालाबों में इकट्ठा किया जाता है। यह पानी तालाबों में पानी के जीवों को बनाए रखने में मदद करता है। यह ताजे पानी की जरूरत बचाता है और ग्राउंड वॉटर लेवल बढ़ाता है। नौ तालाबों के जरिए पानी का बचाव और ग्राउंड वॉटर रिचार्ज किया जा रहा है। सूर्य सरोवर, टैगोर पार्क, कार्यशाला क्षेत्र में तालाब, गोल्फ कोर्स ग्रीन नंबर 10, गोल्फ कोर्स ग्रीन नंबर 3, गोल्फ कोर्स ग्रीन नंबर 2 और कंचनपुर कॉलोनी प्रमुख नौ वाटर बॉडी में जल संरक्षित किया जा रहा है।

कंचनपुर जल निकाय ने उस क्षेत्र की जल भराव की समस्या का समाधान किया है और भूजल स्तर को रिचार्ज करने में भी

मदद की है। बीएलडब्ल्यू ने प्रत्येक डब्ल्यूआरपी में 0.25 एमएलडी क्षमता

की 2 इकाइयां भी स्थापित की हैं।

पानी बचाने और दोबारा इस्तेमाल करने के लिए उठाए गए दूसरे जरूरी कदम

पानी बचाने के और उपाय बताने के लिए एमएनएनआईटी इलाहाबाद ने वॉटर ऑडिट किया। ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर 5 पीजोमीटर लगाकर लगातार ग्राउंड वॉटर लेवल मापने के लिए, 100 और गहरे रिचार्ज बोरेवेल लगाकर ग्राउंड वॉटर बढ़ा रहे हैं, पानी की खपत का सही आंकड़ा जानने के लिए पानी के इस्तेमाल की स्मार्ट मीटरिंग की जा रही है। ग्राउंड वॉटर का सही पानी निकालने के लिए सभी फ्लोमीटर का रेगुलर कैलिब्रेशन किया जा रहा है। पानी का जीरो नुकसान पाने के लिए पुरानी और खराब वॉटर सप्लाय पाइपलाइन को पूरी तरह से रिन्यू करना। इससे 2026 तक पानी की खपत 11.64 एमएलडी से घटकर 6.12 एमएलडी हो जाएगी। जिससे लाखों रूपए की बचत होगी। जल रीसाइक्लिंग और जल संरक्षण के कारण भारी वित्तीय बचत भी सुनिश्चित की जा सकती है। वहीं 2026-27 तक के टारगेट हैं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के जरिए रेन वॉटर का 100 फीसद इस्तेमाल यानी हर साल 6,81,866.4 क्यूबिक मीटर पानी का रेन वॉटर हार्वेस्टिंग से लिया जाए। वॉटर पाइपलाइन में जीरो लीकेज सुनिश्चित की जाए और पूरे कैम्पस की हरियाली को भी बढ़ाया जाए।



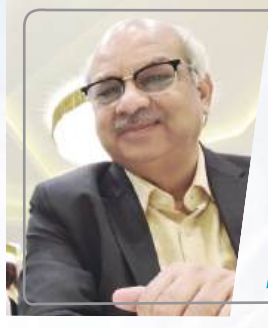
ORGANIZING TEAM



Mr. Sanket Chaturvedi



Mr. Manoj Panday



Mr. Raj Kumar Mittal



Mr. Rajesh Goel



Mr. Abhishek Katiyar



Mr. Ajay Gupta



Mr. Rajiv Malik



Mr. YP Singh



Lalit Mittal



Gaurav Kulshrestha



Abhnav Shrivastva



Bhumi Singh



SINGHANIA UNIVERSITY

📍 Singhania University, Pachheri Bari, Jhunjhunu - 333515, Rajasthan

☎ 9355168880/9810092400 ✉ admissions@singhaniauniversity.ac.in



Singhania University Ranked #1 Emerging Private University in Rajasthan & #8 in India by Outlook University Rankings 2025

Explore from our wide range of 100 + programs



AI & Machine Learning



Law & Legal Studies



Architecture & Design



Engineering and Information Technology



Business, Management & Commerce



Journalism & Communication



Agriculture



Physical Education, Sports & Yoga Sciences

We welcome partners from industry and academia to join us in advancing the Hon'ble Prime Minister of India's vision of inclusive, skill-driven, and future-ready education. Together, let's shape opportunities, drive innovation, and create lasting impact.

To explore collaboration opportunities, write to us at corporate_relations@singhaniauniversity.ac.in



**Dr. Manoj Kumar (IAS Retd.),
President, Singhania University**

“ Singhania University is deeply committed to empowering the youth of our country to become active contributors to India's growth story. We are continuously working to strengthen the industry-academia ecosystem, ensuring our students gain the knowledge, skills and exposure they need for a seamless transition from classrooms to careers. ”



**Scan this QR to
visit our website**

Dhanlakshmi Ramachandra

Karnataka, Bengaluru



Bayer and CSR Business Partner

Based on an average annual rainfall of 1000 mm, a single hectare equipped with TCB or FB structures can store approximately 1 crore litres of water.

The project aims to maintain ecological balance by reducing water wastage and promoting the optimal utilization of existing water resources. By doing so, it supports the protection of natural habitats and the preservation of biodiversity, ensuring long-term environmental health and sustainability.

In villages, Trench cum Bund (TCB), Field Bund (FB), and Pond structures play a crucial role in rain-water harvesting. Based on an average annual rainfall of 1000 mm, a single hectare equipped with TCB or FB structures can store approximately 1 crore litres of water.

These structures not only help in reducing the velocity of surface runoff, thereby preventing soil erosion, but also promote the growth

of diverse species of flora and fauna. This integrated approach enhances groundwater recharge

and contributes to ecological balance in the region.





धवल पांड्या

ट्रस्ट सीईओ, भारतीय मानक ब्यूरो



यह वाई है कुछ खास, भूजल बढ़ाने का एक रास्ता

भारत में किफायती जल संरक्षण प्रयासों को लेकर चर्चा जोरों पर है। इसीलिए भारत का सबसे सस्ता रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सुरत में तैयार किया गया है ताकि हर परिवार अपना सके, जल संरक्षण

किफायती जल संरक्षण के लिए भारत का सबसे सस्ता रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सुरत में तैयार किया गया। महज 1250 रूपए में परिवारों को वर्षा जल उपलब्ध हुआ और समाज में जल स्वावलंबन बढ़ा है।

दरअसल गिरते भूजल स्तर की गंभीर चुनौती को देखते हुए जल संरक्षण को जन-जन तक पहुँचाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के तहत सोमेश्वर ट्रस्ट के धवल पंड्या ने ध्यान केंद्रित किया। उनकी विशेषज्ञता मूल रूप से भूगर्भ जल पुनर्भरण से पहले बहते वर्षा जल से सारे प्रदूषकों (केमिकल, जैविक और अन्य) को दूर करके ही रीचार्ज करना रही है।

ट्रस्ट के सीईओ धवल पंड्या इसी दिशा में भारतीय मानक ब्यूरो की भूगर्भ जल विशेष राष्ट्रीय तकनीकी समिति के सदस्य के रूप में भी सेवा देते हैं। वह मानते हैं कि यह पहल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल के दूरदर्शी दृष्टिकोण से प्रेरित है। जिन्होंने कहा कि देश में लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, वैसे में भूगर्भ गुणवत्ता की जगह उसकी तादाद बढ़ाने पर हालिया ध्यान केंद्रित करना प्राथमिकता है, और यह भी कि इसे ज्यादा खर्च किए बिना किया जाना चाहिए।

इसीलिए कम लागत वाला वाई स्टेनर

बनाया; इस प्रेरणा का परिणाम है एक अनूठा वाई स्टेनर, जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वॉटर रिचार्ज के लिए एक साथ काम करता है।

यह स्टेनर अपने वाई आकार के डिजाइन के माध्यम से, 100 माइक्रोन के हेब्स कोटेड मेष का उपयोग करके, वर्षा के पानी से पत्तियों, मिट्टी और अन्य मलबे जैसे भौतिक कणों को कुशलतापूर्वक छानता है। यह छाना हुआ पानी सीधे भूजल तक पहुँचता है। इसे केवल वर्टिकल

रूप से स्थापित किया जाता है, जिसका पॉकेट नीचे की ओर होना अनिवार्य है।

यह किफायती नवाचार जल संरक्षण को एक सुलभ वास्तविकता बनाता है। जब हर घर इस सरल साधन से बारिश का पानी सहेजेगा, तो इसका सामूहिक प्रभाव भूजल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और भारत को एक जल-सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण होगा। जो कि भारत को जल आत्मनिर्भर बनने में सहायक होगा।





बिंदिया सक्सेना

द शौर्य सोशल वेलफेयर, सोसायटी, बरेली



पानी के लिए हर प्रयास जरूरी है

जीवन के आधार जल के संरक्षण के बिना न तो स्वस्थ समाज की कल्पना की जा सकती है और न ही समृद्ध पर्यावरण की। इसी सोच के साथ जल संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

पानी के लिए की गई मुख्य पहल-टूटे-फूटे नलों की मरम्मत जगह-जगह से रिसते और टूटे नलों को ठीक कराया गया ताकि एक-एक बूंद पानी बर्बाद न हो।

सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना गांवों और सरकारी अस्पताल में साफ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। इसके लिए $0\frac{1}{2}$ के माध्यम से 1100 लोगों को शुद्ध जल दिया गया।

बीसलपुर मार्ग पे किसानों की सिंचाई हेतु नहर से जुड़ी नालियों की सफाई कराई गई और लंबे समय से रुकी सिंचाई को फिर से शुरू कराया गया।

नदियों और तालाबों की सफाई कुआं डंडा एवं मीरगंज में सोसाइटी ने स्थानीय लोगों की सहभागिता से नदियों और तालाबों की सफाई करवाई। इससे V जल स्रोत पुनर्जीवित हुए और जल-जीवों के लिए स्वच्छ वातावरण बना।

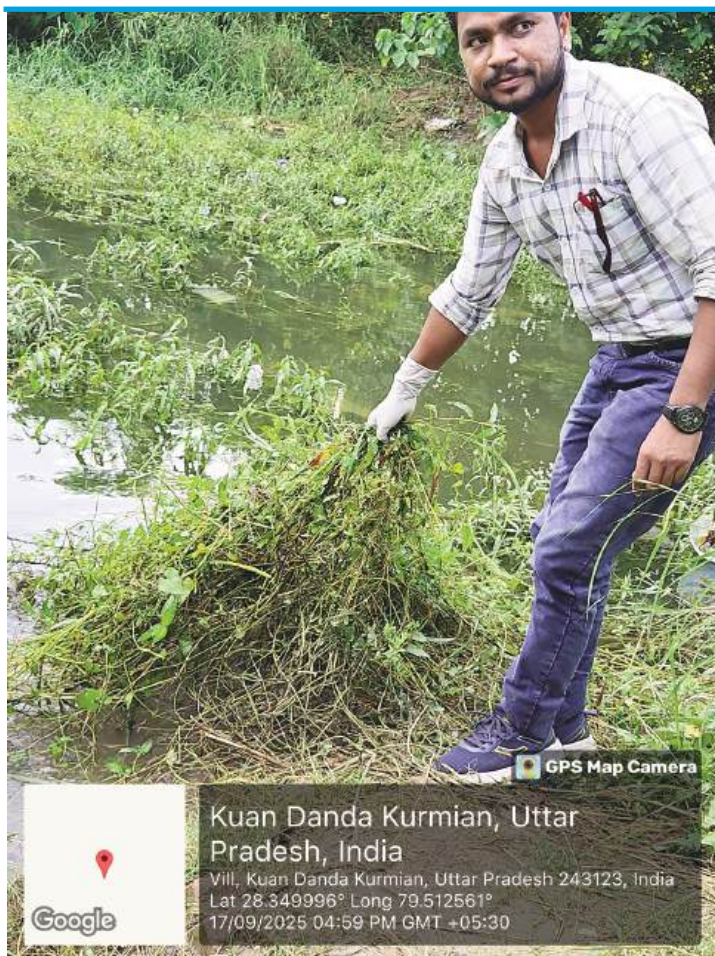
विभिन्न स्कूलों एवम ग्रीन पार्क कॉलोनी, यूनिवर्सिटी में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। जिसमें 2600 पौधों का संरक्षण व देखभाल, गोद लेने की भी जिम्मेदारी ली गई।

जन जागरूकता अभियान लोगों को यह समझाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गए कि जल संरक्षण केवल संस्थाओं की

जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। साथ ही 400 बच्चों, युवाओं को विशेष रूप से इसमें शामिल किया गया। जल है तो कल है।

इसी सोच के साथ सोसाइटी आगे भी अपने कार्य जारी रखेगी।





डॉ. नीलकुमार सुमंतराय देसाई

हरियाली ग्रुप ट्रस्ट, बिलिमोरा (गुजरात)



डॉक्टर जिसकी शिक्षा से जल संरक्षण, जलवायु संरक्षण का पढ़ लिया जन-जन ने पाठ

गुजरात में जल संरक्षण अभियान में 2,260 स्थानों पर वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की। सरकारी, अर्ध-सरकारी संस्थान जैसे कोर्ट, मामलतदार कार्यालय, पुलिस स्टेशन, स्कूल एवं कॉलेज शामिल हैं। इससे वर्षा के जल का स्थानीय भूजल स्तर पर सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

गुजरात के नवसारी “वनगाम क्षेत्र में विक्रम संवत् 1936 (1879 ई.) में निर्मित एक पुराने कुएँ का जीर्णोद्धार” किया गया, और उसके साथ वर्षा जल संचयन प्रणाली लागू की गई। पुनर्स्थापित कुआं अब लगभग ‘20 लाख लीटर (2 मिलियन लीटर)’ पानी संग्रहित करने में सक्षम है, जिससे यह स्थानीय निवासियों के लिए पीने योग्य और घरेलू उपयोग हेतु अत्यंत उपयोगी बन गया है।

यहीं पर ‘100 पेड़ों का एक मियावाकी वन’ भी विकसित किया गया, जिसे जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल द्वारा भी सराहा गया।

गुजरात के डांग जिले के वसुरना गांव में, ‘1,800 फुट गहरे मृत बोरवेल का रिचार्ज’ कर दो कुओं को पुनर्जीवित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र के भूजल स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। वहीं, बनासकांठा जिले में भी कई जल संचयन परियोजनाएं प्रारंभ की गईं।

वृक्षारोपण के क्षेत्र में, मियावाकी पद्धति द्वारा विकसित किए वन

वर्ष 2022 में बिलिमोरा के श्मशान भूमि पर दूसरा मियावाकी वन (450 पेड़)

वर्ष 2023 में वलसाड में तीसरा मियावाकी



वन (5,000 पेड़)

वर्ष 2024 में गायत्री परिवार के सहयोग से नवसारी में चौथा मियावाकी वन (6,280 पेड़)

वर्ष 2025 में डांग जिले के वसुरना गांव के हेतलदादी आश्रम में एक और वन (1,000 पेड़)

अब तक कुल मिलाकर लगभग ‘15,000 पेड़ लगाए जा चुके हैं’। पेड़ पानी के प्राकृतिक संचयक होते हैं, एक अनुमान के अनुसार एक पेड़ अपने जीवनकाल में लगभग ‘1,000 गैलन पानी’ का संरक्षण करता है। इस प्रकार, इन पहलों के माध्यम से लगभग ‘15 मिलियन गैलन जल संरक्षण’ संभव हुआ है।

यह परियोजना न केवल पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण है, बल्कि सामुदायिक भागीदारी और सतत विकास की दिशा में एक प्रेरणादायक प्रयास भी है। इस पहल ने नवसारी, वलसाड और डांग जिलों में जलस्रोत पुनर्जीवन और हरियाली बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।



प्रो.डॉ. एच.एम. पाटिल

प्रिंसिपल, एमजेपीवी कॉलेज, अकरानी तहसील, नंदुरबार



सतपुड़ा के पर्वतीय इलाकों में प्रोफेसर की जल सारक्षता

पहाड़ी भूभाग, अनियमित वर्षा और भीषण जल संकट से ग्रस्त क्षेत्र में वर्षा जल संरक्षण की पहल से बदलती तस्वीर।

नंदुरबार जिले के सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में स्थित अकरानी तहसील पहाड़ी भूभाग, अनियमित वर्षा और भीषण जल संकट से ग्रस्त है। कृषि उत्पादकता ऐतिहासिक रूप से कम रही है, और आदिवासी समुदाय - मुख्यतः पवारा और भील - वर्षा आधारित खेती पर निर्भर हैं। इस समस्या के समाधान के लिए, डॉ. हीरालाल मंगल पाटिल ने नमामि सतपुड़ा मिशन और जल साक्षरता समिति अकरानी के तहत कई सामुदायिक जल संरक्षण कार्यों की शुरुआत और मार्गदर्शन किया। कोविड (2020-21) के दौरान 22 वनराई बांधों का निर्माण किया और क्रम सतत, जारी है। अकरानी तहसील के विभिन्न गांव जिनमें बोरवन, कुकलाटपाड़ा और निमजारी पाड़ा आदि शामिल हैं। यहां ग्रामीणों, एनएसएस स्वयंसेवकों और स्थानीय युवाओं को स्वैच्छिक श्रमदान के लिए प्रेरित किया गया। रबी फसल क्षेत्र के लगभग 225 एकड़ क्षेत्र में जल उपलब्धता सुनिश्चित की गई।

इससे करीबन 7,300 से अधिक लोगों और असंख्य पशुओं के लिए पेयजल की उपलब्धता में सुधार हुआ। मानसून के बाद भूजल स्तर में 0.5-1.2 मीटर की वृद्धि हुई।

सतत समोच्च खाइयां (सीसीटी)

कुकलाटपाड़ा और निमजारी पाड़ा के आसपास की पहाड़ी ढलानें। अपवाह को धीमा किया,

अंतःस्यंदन को बढ़ावा देना और मृदा अपरदन को नियंत्रित करना।

लगभग 10,000 रैखिक मीटर खाइयां हाथ से और जेसीबी द्वारा खोदी गईं। हल्की ढलानों पर नियमित सीसीटी (50 सेमी .30 सेमी) य अधिक ढलानों पर गहरी सीसीटी (75 सेमी .50 सेमी) की तैयार की गई। प्रभाव हुआ कि मृदा नमी प्रतिधारण में वृद्धि और वनस्पति आवरण में सुधार हुआ। मौसमी कुओं और हैंडपंपों में भूजल पुनर्भरण में सहायता की गई।

पत्थर की मेड़बंदी और कृषि मेड़बंदी
कुकलाटपाड़ा और निमजारी पाड़ा में कृषि भूखंडों के किनारे। मृदा अपरदन को रोकना, गाद

जमाव को कम करना और मृदा पोषक तत्वों को बनाए रखना। 1000 मीटर से अधिक पत्थर की मेड़बंदी और 30 हेक्टेयर कृषि मेड़बंदी पूरी हुई। पत्थर पास की पहाड़ियों से प्राप्त किए गए, समुदाय ने श्रमदान किया। इससे ऊपरी मृदा क्षरण में कमी आई और भूमि उत्पादकता में 20-25 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि भूमि की स्थिरता में वृद्धि।

सामुदायिक और संस्थागत भागीदारी के साथ प्रोफेसर पाटिल के मार्गदर्शन में स्थापित जल साक्षरता समिति अक्राणी ने इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई। इन कार्यों में जायंट्स ग्रुप शहादा,



ग्राम पंचायत राजबर्डी, पानी फाउंडेशन, एनएसएस स्वयंसेवक और छात्र ने सहायता प्रदान की और सामाजिक प्रभाव रहा कि आदिवासी युवाओं और ग्रामीणों में स्वामित्व की भावना, टीम वर्क और पारिस्थितिक जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सका।

लाभार्थी और क्षेत्र पर प्रभाव

कुल शामिल गांव, 22 (कुकलतपाड़ा, निमजारी पाड़ा, बोरवान, राजबर्डी क्षेत्र सहित) लाभ प्राप्त कुल परिवाररू लगभग 500 से अधिक परिवार सीधे लाभान्वित जनसंख्या, 5000 से अधिक प्रभावित कृषि क्षेत्र: लगभग 225 एकड़ (रबी और खरीफ)

लाभ प्राप्त पशुधन: लगभग 2,000 पशु मानसून के बाद भूजल में 0.5-1.2 मीटर की वृद्धि

प्रमुख जल संरचनाएं: 22 वनराय बांध, सीसीटी नेटवर्क, पत्थर के बांध-चेक बांध संबद्ध गतिविधियां: वृक्षारोपण (5,000 से अधिक पौधे), घास रोपण (20 हेक्टेयर), जागरूकता शिविर

प्रमुख परिणाम

-पहाड़ी आदिवासी क्षेत्रों में सूखा निवारण के लिए एक अनुकरणीय मॉडल स्थापित किया गया।

-पारंपरिक जल संचयन को वैज्ञानिक जलग्रहण सिद्धांतों के साथ जोड़ा।

-जल साक्षरता और जिम्मेदारी से उपयोग की संस्कृति को बढ़ावा दिया।

-बेहतर हरित आवरण, कम अपवाह और जैव विविधता पुनर्स्थापन जैसे पारिस्थितिक लाभ उत्पन्न किए।



एकनाथ मोतीलाल माळतकर

जामदा, महाराष्ट्र



पानी आया तो लौट आए गांव में खुशियों के दिन

ग्रामवासियों, युवाओं को संगठित करके सामूहिक श्रमदान कराया, और 'मिशन 500 कोटी लिटर' जैसे व्यापक अभियान में जलमित्र के रूप में अहम भूमिका निभाई।

संघर्ष से सामूहिक परिवर्तन तक की यात्रा: एक ग्रामीण किसान परिवार में जन्म लेकर आपने अपने अनुभवों को समाजहित के कार्य में रूपांतरित किया। गांव में पढ़ाते हुए बदलते मौसम चक्र, घटती बारिश, सूखा, अकाल की चुनौतियों को देखा। किसानों के संघर्ष, खेती पर निर्भरता, मजदूरों की दिक्कतें देखीं; काम की कमी, पानी की परेशानी से पलायन, बच्चों की शिक्षा में आने वाली बाधाएं भी देखीं। अनाज की सही कीमत न मिलने, कर्ज में डूबने और फिर जीवनलीला समाप्त करने जैसे वाक्यों ने मेरे भीतर जल के प्रति गंभीरता को बढ़ाया फिर मैंने कुछ करने की ठान ली।

शिक्षक और समाजसेवक का अनोखा संगम: शिक्षक के रूप में बच्चों को ज्ञान देने के साथ-साथ आपने गांववालों को 'जलसाक्षरता' के काम को अंजाम दिया।

पानी फाउंडेशन के माध्यम से ठोस कार्य किए: 'सत्यमेव जयते वॉटर कप' प्रतियोगिता में दूसरा पुरस्कार जीतना और उस पुरस्कार राशि छह लाख रुपये को अगले वर्ष के कार्य में लगाना आपके 'निःस्वार्थ समर्पण' को दर्शाता है।

सकारात्मक परिणाम: भूजल स्तर में वृद्धि, किसानों की आय में सुधार, पलायन में कमी और गांवों में समृद्धि, ये आपके प्रयासों की

ठोस उपलब्धियां हैं।

आपका यह कार्य 'रालेगणसिद्धी' और 'हिवरेबाजार' जैसे आदर्श ग्रामों की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है।

वर्ष 2001 में मैंने जामदा तहसील चालीसगाव जिल्हा जलगांव गांव के पास स्थित भराडी नदी पर वनराई बंधारा बांधने का श्री गणेश किया जिससे पानी के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि देखे गई इस प्रकार का काम बड़े पैमाने पर करने की आकांक्षा थी

वर्ष 2018 में जब महाराष्ट्र के कई हिस्सों में पानी की समस्या गहरा गयी थी पानी फाउंडेशन की प्रतियोगिता के माध्यम से मुझे अपने सपने को पूरा करने का अवसर मिला मैंने जामदा गांव में



अन्य युवा के साथ मिलकर दो किमी तक भराडी नदी की खुदाई की 3 एकड़ जमीन में सीसीटी बनाये, 2 लूज बोल्टर स्ट्रक्चर तैयार किए और एक गैबीयन बांध बनाया।

कार्य में युवाओं ने श्रमदान किया और दान दाताओं ने आर्थिक योगदान दिया साथ ही माती बांध का निर्माण, विहीर पुनर्भरण, बांधबर्धस्ती और पुराने बंधारों की मरम्मत जैसे काम भी गांववासीयों की एकता श्रमदान और आर्थिक सहाय्यता से संभव हुए। इस जलसंधारण के प्रयास ने मनसंधारण भी किया जिसे लोगो में मिट्टी पानी और खेती को लेकर जागरूकता और सजगता का माहोल बना। आगे चलकर डॉ. उज्ज्वल कुमार चव्हाण ने 40 गांव तहसील के जलमित्र को संगठित और प्रशिक्षित करके मिशन 500 करोड़ लीटर जलसंधारण का निर्माण किया इस मिशन के अंतर्गत एक पांच पाटील के रूप में कार्य कर रहा हूं। मिशन के तहत जलगांव धुलिया और संभाजी नगर, बुलढाणा यवतमाल जिलों के 27 गांव में मैंने जलसंधारण का काम किया है जिसमें नाला खोलीकरण, रुंदीकरण, विहीर पुनर्भरण पुराने बांध के दुरुस्ती, नये बांध बनाना, खेत तालाब बनाना, जलतारा इत्यादी कार्य का समावेश है। मुख्यतः भराडी नदी और गड़गड़ नदी के क्षेत्र में यह काम किया है।

इसके परिणाम स्वरूप 70 करोड़ लीटर

पानी की बचत हुई है जिसे भूजलस्तर में वृद्धि आई है नदी की गाद को हमने कृषि क्षेत्र में खाद के रूप में उपयोग किया जिसे खेतों की उर्वरकता बढ़ी और किसानों का उत्पादन भी बढ़ गया। इसके साथ ही 12 किलोमीटर रास्ते बने जिससे किसान लाभान्वित हैं। अब इस क्षेत्र में किसान साल के उत्पादन ले पा रहे हैं पशु को चारे की कमी नहीं है, जिसे दुग्धोत्पादन में वृद्धि हुई है पशुधन बनने से खाद की उपलब्धता भी बढ़ी है और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है लोगो का पलायन रुक गया है और गांव में पुनरागमन शुरू हो गया है जिसे किसानों के बच्चे अच्छे से पढ़ लिख पा रहे हैं।

मेरा जन्म 'एक ग्रामीण इलाके में गरीब किसान के परिवार में हुआ है। मैंने खेती और गांव की मुश्किलें करीब से देखी और झेली है।

जिस गांव में जलसंधारण के काम हुए थे वहां यह दुःचक्र रूप गया है रालेगणसिद्धी हिवरेबाजार और पाटोदा जैसे गांव में किये गये प्रयोग के सकारात्मक परिणाम देखे उनगाव का अध्ययन करके ऐसेही उपक्रम को अन्य स्थान पर भी लागू करने का निश्चय किया। कुछ मिलाकर गांवों में समृद्धि का माहोल है ये सारी चीजें मुझे आगे और भी काम करने की प्रेरणा देती है। मेरे इस जलसंधारण के कार्य में मुझे मेरी पत्नी आरस्ता मालतकर का पूरी तरह से सहयोग मिला उसकी वजहसे मेरा ये काम अविरत चल रहा है।



तरुण वैद्य

ग्रीन टाइगर्स, बैतूल



टाइगर्स जो बचाते हैं, बनाते हैं जल जीवन का सुखद कल

ग्रीन टाइगर्स ने जब कदम बढ़ाए, नदियां साफ हुईं, गर्मियों में जल संकट घटा, भू-जल स्तर में सुधार हुआ, पर्यावरण-संतुलन मजबूत हुआ, समाज में जल बचत के प्रति जागरूक हुए लोग...

बैतूल जिले में जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यरत 'ग्रीन टाइगर्स बैतूल' संगठन बीते वर्षों में एक महत्वपूर्ण जन-संगठन के रूप में उभरा है। जिले की लगभग '65 फीसद जनसंख्या नदियों के जल पर निर्भर' है तथा '10 में से 8 ब्लॉक' पेयजल की आपूर्ति के लिए इन्हीं जल-स्रोतों पर आधारित हैं। ऐसे में नदियों, तालाबों और भू-जल का संरक्षण यहां की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ग्रीन टाइगर्स ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं, जो आज परिवर्तन का आधार बन रहे हैं।

बोरीबांध निर्माण: सरल और प्रभावी तकनीक

ग्रीन टाइगर्स ने सबसे पहले जिले के कई गांवों में 'बोरीबांधकों का निर्माण' कर नदी जल संग्रहण को बढ़ावा दिया।

रेत से भरी बोरियों को नदी के उथले हिस्सों में बांधकर छोटी-छोटी जल-अवरोधक संरचनाएं बनाई गईं।

इससे 'जल धारा धीमी हुई', पानी 'लंबे समय तक रुका', और आस-पास के क्षेत्रों में 'भू-जल स्तर में वृद्धि' हुई।

गर्मियों में भी गांववासियों को पेयजल



उपलब्ध रहा, जिससे जल संकट में कमी आई।

संगठन ने नदियों को स्वस्थ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की जिससे नदियां अधिक स्वच्छ हुईं, प्रदूषण घटा और जल प्रवाह में सुधार आया।

नदियों की नियमित 'सफाई के लिए विशेष अभियान'

नदियों से 'गाद हटाना'

'तट संरक्षण कार्य'

'प्लास्टिक-मुक्त नदी अभियान'

कुओं, बावडियों व तालाबों का पुनर्जीवन'

बैतूल के कई गांवों में वर्षों से उपेक्षित पारंपरिक जल-स्रोतों को फिर से सक्रिय किया गया।

पुराने कुओं का 'गहरीकरण', 'सफाई', 'दीवारों की मरम्मत'
तालाबों की 'डिसिल्टिंग' (गाद हटाना)
इन प्रयासों से ग्रामीणों को स्वच्छ और पर्याप्त जल उपलब्ध होने लगा।

वर्षा जल संचयन संरचनाएं

ग्रीन टाइगर्स ने वर्षा जल को भू-जल रिचार्ज में बदलने के लिए व्यापक स्तर पर काम किया;

-चेक-डैम

-परकोलेशन पिट

-सोख गड्डे

-'छोटे जलाशय

इन संरचनाओं से वर्षा जल सीधे जमीन में समाहित होने लगा और भू-जल स्तर लगातार सुधार की ओर अग्रसर हुआ।

इसके साथ ही जनजागरूकता अभियान चलाए ताकि इन कार्यों के प्रति जनभावनाओं को जोड़ा जा सके।

-लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए संगठन ने निरंतर जागरूकता कार्यक्रम चलाए।

-रैलियां

-नुक्कड़ नाटक

-पोस्टर प्रतियोगिताएं आयोजित की

-स्कूलों तथा कॉलेजों में कार्यशालाएं

–‘जल बचाओ’ अभियान

इन गतिविधियों से लोगों में जल संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी और सकारात्मक सोच विकसित हुई।

कृषि क्षेत्र में जल-प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए किसानों को कम पानी में बेहतर खेती के लिए प्रेरित किया गया

–टपकन सिंचाई (Drip Irrigation)

–स्प्रिंकलर प्रणाली

–जल-संचयन आधारित खेती तकनीकें

–इन प्रयासों से पानी की बचत हुई और

खेती अधिक उत्पादक बनी। वृक्ष जल संरक्षण के प्राकृतिक योद्धा हैं। ग्रीन टाइगर्स ने यह समझा कि पानी को बढ़ाना है तो वृक्ष जरूरी हैं इसलिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाए।

–गांव-गांव में वृक्षारोपण

–नदी किनारे पौधारोपण

–पौधों की सुरक्षा के लिए संरक्षक बनाए

पेड़ों ने मिट्टी को बांधा, वर्षा जल को रोका और जल-स्रोतों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इन सभी प्रयासों के कारण ग्रीन टाइगर्स न केवल जल संरक्षण के क्षेत्र में एक प्रेरक संगठन बना है, बल्कि यह मॉडल अन्य जिलों के लिए भी अनुकरणीय है।



हिमांशु नागपाल

आईएस, वाराणसी



नाद, मटुका को वाराणसी में मिला नया जीवन

वाराणसी की पहचान गंगा से जुड़ी है, और इसके सांसद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। जिले की समृद्धि और स्थिरता में जल संसाधनों की अहम भूमिका रही है। इसी दिशा में यहां के भूजल स्तर सुधार, जल भंडारण क्षमता में वृद्धि, तथा मटुका और नाद नदियों के पुनर्जीवन ने वाराणसी को जल प्रबंधन का आदर्श मॉडल बना दिया है।

नदियों का पुनर्जीवन-जीवन की धारा फिर बह चली

मटुका नदी, जो लगभग 27 किलोमीटर लंबी है, और नाद नदी, जो करीब 30 किलोमीटर लंबी है, कभी अतिक्रमण और उपेक्षा के कारण लगभग विलुप्त हो चुकी थीं। इन दोनों नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया।

अतिक्रमण हटाया गया, नदियों की साफ-सफाई की गई, और जल धारा को पुनर्स्थापित करने के लिए चेक डैम बनाए गए। आज ये दोनों नदियाँ फिर से लबालब जल से भरी हैं, जिससे आसपास के हजारों किसानों को सिंचाई का लाभ मिल रहा है और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है।

वर्षा जल संचयन- हर बूंद का सम्मान
शहर ने वर्षा जल संचयन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। इसके तहत:

8050 से अधिक पुनर्भरण गड्ढे बनाए गए।

1800 वर्षा जल संचयन यूनिट्स स्थापित की गईं। सभी विद्यालयों में वर्षा जल संचयन



प्रणालियां सुनिश्चित की गईं, ताकि हर संस्था जल संरक्षण में सहभागी बने। इन प्रयासों से न केवल बरसाती जल का उपयोग बढ़ा, बल्कि शहर के समग्र भूजल स्तर में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ।

अमृत सरोवर व तालाबों का नवजीवन

वाराणसी में अमृत सरोवर योजना के तहत 403 अमृत सरोवर बनाए गए, जो स्थानीय जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के केंद्र बने हैं। इसके साथ ही, शहर में 700 से अधिक तालाबों की पहचान की गई और उनका पुनर्ग्रहण (Reclamation) किया गया, जिससे अतिरिक्त जल भंडारण क्षमता में भारी वृद्धि हुई।

अप्रयुक्त बोरवेल व चेक डैम से पुनर्भरण

अप्रयुक्त एवं विफल हैंडपंप बोरवेल को भी जल पुनर्भरण के लिए दोबारा उपयोगी बनाया गया। अब तक 1043 बोरवेल ऐसे पुनर्जीवित किए गए हैं, जो भूजल स्तर सुधार में सहायक बने हैं। इसके साथ ही 412 से अधिक चेकडैम, पक्के और कच्चे-नदियों व नालों पर बनाए गए, जो वर्षा जल को रोककर भूमिगत जल को रिचार्ज

कर रहे हैं।

वेटलैंड्स का संरक्षण-जैव विविधता की रक्षा
वाराणसी प्रशासन ने दोमैला, काठीरांव, गजोखर और उंडी जैसे क्षेत्रों में वेटलैंड्स का पुनरुद्धार किया है। इन प्रयासों से क्षेत्र की जैव विविधता को नया जीवन मिला है और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित हुआ है।

सकारात्मक प्रभाव और उपलब्धियां

इन पहलों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पिंडरा विकासखंड, जिसे पहले गंभीर श्रेणी में रखा गया था, अब अर्ध-गंभीर श्रेणी में आ गया है, जो भूजल स्तर में उल्लेखनीय सुधार का प्रमाण है।

वाराणसी में जल पुनरुद्धार और संरक्षण के कार्य शहर की स्थिरता, पर्यावरणीय जागरूकता और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण हैं। इन पहलों ने न केवल भूजल स्तर सुधारा है, बल्कि वर्षा जल संचयन, सरोवरों के संरक्षण और वेटलैंड विकास के माध्यम से एक सतत जल प्रबंधन मॉडल प्रस्तुत किया है।

वाराणसी आज भारत ही नहीं, बल्कि विश्व के लिए भी एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभरा है—जहां परंपरा और आधुनिकता मिलकर 'हर बूंद में जीवन' का संदेश दे रही हैं।



Before



Before



Rainwater Harvesting Structures installed in Government Buildings



After

Rejuvenation of Nadi River



After

Pond Rejuvenation



Improvement of Ponds by Cleaning Water Hyacinth and Floating Wetlands

कामिनी कुमारी

बेगूसराय, बिहार



ग्रामीण महिला ने रच दिया प्रेरणा का एक समृद्ध सागर

दो साल में पुनर्भरण गड्ढों के साथ-साथ तालाब, नदियों को दिया पुनर्जीवन, जलकुंभी से बना दी खाद, नमी से दीमक का किया सफाया....

पानी केवल जीवन नहीं है, यह आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और अस्तित्व का आधार है। इसी भावना से प्रेरित होकर झारखंड की कामिनी कुमारी ने अपने संगठन आप का आंचल के माध्यम से वह कार्य किया है, जो आज ग्रामीण भारत में जल आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुका है। कामिनी कुमारी का सफर एक साधारण ग्रामीण महिला से लेकर जल प्रहरी बनने तक का रहा है। जब उन्होंने अपने क्षेत्र में लगातार गिरते भूजल स्तर और सूखती नदियों को देखा तो तब उन्होंने यह प्रण लिया कि पानी के लिए अब किसी और का इंतजार नहीं होगा। उन्होंने महिलाओं, युवाओं और किसानों को संगठित कर श्रमदान के माध्यम से जल पुनर्भरण और नदी पुनर्जीवन की एक अनूठी यात्रा शुरू की।

पिछले दो वर्षों में, उनके नेतृत्व में समुदाय ने 5000 जल पुनर्भरण गड्ढे, 16 तालाब और बाया व बलान जैसी सहायक नदियों का पुनर्जीवन किया है। नदियों से निकले जलकुंभी को हरे कचरे को फेंकने के बजाय उन्होंने उसे प्राकृतिक खाद में बदलकर खेतों में प्रयोग किया, जिससे मिट्टी की नमी बढ़ी दीमक की समस्या खत्म हुई और उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आज 68 हेक्टेयर भूमि पर यह जैविक अपशिष्ट खाद प्रयोग में है, और 1900 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती

तथा 1000 एकड़ पर जल संवेदनशील फसलों का प्रसार हुआ है। पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक दृष्टिकोण का सुंदर संगम किया, जल पुनर्भरण गड्ढों के साथ वृक्षारोपण कर उन्होंने हर गड्ढा, एक हरियाली का मॉडल खड़ा किया, जिससे मिट्टी की दरारें घटीं और जलधारण क्षमता बढ़ी।

उनका प्रयास केवल जल संरक्षण तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने इसे महिलाओं के

नेतृत्व, युवाओं की भागीदारी और सामुदायिक स्वामित्व के साथ जोड़ दिया। इन कार्यों के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय संस्थाओं ने सम्मानित किया है। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है, हमारे गांवों में पानी की कमी नहीं, केवल प्रबंधन की कमी है। इसी सोच ने उन्हें एक ऐसी पर्यावरण संरक्षिका बना दिया है जो जल के साथ-साथ मिट्टी, जैव विविधता और समुदाय की आत्मा को भी पुनर्जीवित कर रही हैं।





किशोर जायसवाल

जल संरक्षण

जल संरक्षण से अनोखा रिश्ता, समर्पण, सामुदायिक भागीदारी से तैयार हुई परिवर्तन की लहरें



जल संरक्षण गुजरात के बावड़ियों से लेकर राजस्थान के जोहड़ों तक, दक्षिण भारत के मंदिर तालाबों से लेकर बिहार के अहार पाइन प्रणाली तक हमारे देश ने सदैव यह समझा है कि 'जल केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन और आजीविका की जीवनरेखा है।

जल आत्मनिर्भरता 2047 के प्रति प्रतिबद्धता

पिछले कई वर्षों से उन्होंने परंपरागत जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने और भूजल पुनर्भरण के लिए सतत प्रयास किए हैं। उनका जल संरक्षण का दृष्टिकोण पारंपरिक भारतीय जल प्रबंधन की बुद्धि को आधुनिक स्थानीय तकनीकों के साथ जोड़ता है, ताकि जल की हर बूंद का मूल्य समझा जा सके। उनका यह कार्य केवल तालाबों, झीलों और नदियों के पुनर्जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि 'सामाजिक चेतना के विकास' तक विस्तृत है। स्थानीय 'पंचायतों, विद्यालयों, स्वयं सहायता समूहों और युवा स्वयंसेवकों' को जोड़कर जल संरक्षण को एक 'जन भागीदारी आंदोलन' का रूप दिया है। जो प्रधानमंत्री जी की जनभागीदारी की अवधारणा का सजीव उदाहरण है।

पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन: उपेक्षित तालाब, बावड़ियां और नहरें साफ कर गहरी की गईं और फिर से उपयोग योग्य बनाई गईं।

भूजल पुनर्भरण: चेक डैम, कंटूर बंडिंग और सामुदायिक वर्षा जल संचयन गड्ढों के

माध्यम से हजारों लीटर जल को पुनर्भरण हेतु संरक्षित किया गया।

सतत कृषि: बेहतर सिंचाई व्यवस्था से किसानों की पैदावार बढ़ी और वर्षा पर निर्भरता कम हुई।

शहरी भागीदारी: नगरों में विद्यालयों, सरकारी भवनों और आवासीय परिसरों में छतों पर वर्षा जल संचयन प्रणालियां स्थापित की गईं।

जनजागरूकता अभियान: जल चौपाल, भित्तिचित्र (दीवार पेंटिंग) और 'इको-क्लब्स'





के माध्यम से हजारों नागरिकों को जल संरक्षण की दिशा में प्रेरित किया गया।

इन प्रयासों के परिणाम केवल भौतिक नहीं हैं कृ पुनर्जीवित तालाबों और बहती नदियों के साथ-साथ एक 'सजग समाज' का निर्माण भी हुआ है, जो अपने साझा संसाधनों की रक्षा में

सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं जल शक्ति अभियान, नमामि गंगे, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन के अनुरूप आगे बढ़ाया है। जिला प्रशासन, विकासखंड अधिकारियों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ समन्वय स्थापित किया, जिससे

पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुआ। साथ ही, उन्होंने विद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में जल साक्षरता अभियान चलाकर विद्यार्थियों में जल संरक्षण के प्रति चेतना जागृत की, ताकि अगली पीढ़ी भी 'जल प्रहरी' के रूप में विकसित हो सके।



मधुकर स्वयंभू, चंद्रशेखर

प्रकृति आधारित समाधान विशेषज्ञ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

इनोवेशन से सॉल्यूश तक का सफर है मधुकर



इनोवेशन, पर्यावरणविद्, पारिस्थितिकीविद्, आविष्कारक, उद्यमी, तथा 'जैव विविधता संरक्षण के समर्थक ने 60 जलाशयों का किया सफल पुनर्जीवन।

भारत में 60 से अधिक जलाशयों का सफल पुनर्जीवन किया है, जो '300 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल' में फैले हैं। 'तकनीकी पेशेवर से पर्यावरण योद्धा तक की यात्रा की बात करें तो लगभग दो दशकों तक मधुकर स्वयंभू भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया में एक 'आईटी कम्युनिकेशन नेटवर्क विशेषज्ञ' के रूप में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ जुड़े रहे। साल 2016 में उन्होंने अपनी सफल कॉर्पोरेट करियर को त्यागकर सस्टेनबिलिटी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कार्य करने का निश्चय किया। वैदिक सृजन एक जलवायु प्रौद्योगिकी स्टार्टअप बनाया और सहयोगियों के साथ मिलकर 'वैदिक सृजन एलएलपी बनाया जो कि भारत में एक क्लाउडमेट टेक स्टार्टअप के तौर पर सामने आया। यह संगठन 'वैदिक विज्ञानों पर आधारित एक दशक लंबे अनुसंधान' के पश्चात स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य वैश्विक समस्याओं के लिए 'सतत और समग्र समाधान खोजना है।

नवाचार और आविष्कार: मिट्टी, जल और वायु के पुनर्स्थापन हेतु कई 'प्रकृति आधारित प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं, जो प्राकृतिक जल निकायों और वेटलैंड्स को केंद्र में रखकर कार्य करती हैं।

इनमें प्रमुख हैं....

-कॉवोनोमिक्स टेक्नालोजी

-इकोलाइनिंग

-इकोडेरजिंग

-इकोडेरन

-इंटीग्रेटेड एंड सिम्बॉयोटिक एंड फार्मिंग

इनके अतिरिक्त कई अन्य तकनीकों पर कार्य जारी है।

भारत में 60 से अधिक जलाशयों का सफल पुनर्जीवन किया है, जो '300 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल' में फैले हैं। इन परियोजनाओं से अरबों लीटर अपशिष्ट जल को 'उपयोगी जल' में परिवर्तित किया गया, कई लाख लीटर भूजल का पुनर्भरण हुआ, 'मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आई, और जैव विविधता का

संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। इन प्रयासों से लगभग '20 लाख से अधिक लोगों' को वायु प्रदूषण से उत्पन्न श्वसन रोगों तथा जल जनित रोगों से राहत मिली, जिससे उनके वार्षिक स्वास्थ्य खर्च में उल्लेखनीय बचत हुई और समग्र 'स्वास्थ्य व समृद्धि सूचकांक' में सुधार हुआ।

राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर योगदान इन कार्यों पर व्याख्यान देने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संस्थानों, मंचों, विश्व विद्यालयों व संगठनों में आमंत्रित किया गया है। इनमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विश्व बैंक, ग्लोबल लीडरशिप समिट, सीओपी, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सम्मेलन शामिल हैं।





आकांक्षा सैमूल

प्रधानाचार्या, पी.एम. केन्द्रीय विद्यालय नं. 1, ऑर्डनेंस फैक्ट्री, कटनी, मप्र

इनोवेशन, प्रोत्साहन के प्रयास से कटनी के बच्चे भर रहे धरती का जल भंडार



खनिज संपन्न कटनी क्षेत्र में पूरे साल जल-संकट की समस्या है, वहां पी.एम. श्री के.वी. कटनी ने जिम्मेदारी निभाई और जल संरक्षण, हरित विकास और विद्यार्थियों में पर्यावरण-जागरूकता बढ़ाने के लिए अनेक नवाचार किए।

ड्रिप सिंचाई प्रणाली-गर्मियों 2023 में विद्यालय ने त्यागे गए 'आई.वी. सेट' और 'ग्लूकोज बोतलों' से 'शून्य लागत ड्रिप सिंचाई प्रणाली' विकसित की। इस उपाय से पौधों को नियंत्रित जल आपूर्ति सुनिश्चित हुई। यह पहल शिक्षा मंत्रालय व के.वी.एस. मुख्यालय द्वारा सराही गई।

वर्षा जल संचयन एवं भूजल पुनर्माण

-भवनों की छतों से वर्षा जल को छिद्रित नालियों से जमीन में पहुँचाने की व्यवस्था।

-परिसर की सीमाओं पर पुनर्भरण गड्ढे तैयार किए गए।

-पुराने फव्वारे को 'कैच द रेन' कार्यक्रम के अंतर्गत वर्षा जल कुएं में परिवर्तित किया गया।

-1000 से अधिक पौधे लगाए गए जिससे भूजल स्तर में सुधार हुआ।

जनसहभागिता: सेव वॉटर अभियान

-विद्यालय के बच्चों ने कटनी साउथ रेलवे स्टेशन पर हर पंद्रह दिन में 'पानी बचाओ अभियान' चलाया।

यात्रियों को जागरूकता पर्चे वितरित किए, 'हस्तनिर्मित पोस्टर प्रदर्शित किए व संवाद के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश दिया।

इससे छात्रों में आत्मविश्वास, सामाजिक

उत्तरदायित्व और संप्रेषण कौशल विकसित हुए।

वैज्ञानिक निगरानी: पाईजोमीटर परियोजना

अटल टिंकरिंग लैब के मार्गदर्शन में छात्रों ने विद्यालय के 120 फीट बोरवेल पर 'पाईजोमीटर' लगाया।

जहां जनवरी 2025 में जल स्तर 5.4 फीट मापा, 'जुलाई 2025 में जल स्तर 17.5 फीट हो गया। यह सुधार विद्यालय की वर्षा जल संचयन योजनाओं की सफलता का प्रमाण है।

बागवानी एवं अपशिष्ट प्रबंधन

जैविक कचरे से 'कम्पोस्ट व वर्मी कम्पोस्ट' तैयार किया।

औषधीय व रसोई उद्यान बनया, 'कचरे से खाद निर्माण किया व फफूंदी तकनीक का प्रयोग किया। इन पहलों ने विद्यालय परिसर को हरित, सुंदर और पर्यावरणीय दृष्टि से स्वावलंबी बनाया।

विद्यालय को 'चेंज मेकर अवार्ड' व 'ग्रीन लीफ अवार्ड' जैसे सम्मान प्राप्त हुए हैं, जो इसके सतत विकास व पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पण को प्रमाणित करते हैं।





नेहपाल सिंह

गांव- श्रीनगर बंधेन, पोस्ट- राजगढ़, जिला- अलवर, राज्य- राजस्थान,

क्षेत्र में अनेकों स्थानों पर सभी के सहयोग से जलाशय बनाए



स्कूल व कॉलेज में छात्र-छात्राओं को जल बचाने का आह्वान कर व जल के महत्व को बता रहे, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे

मैं नेहपाल सिंह राजस्थान के अलवर जिले में राजगढ़ तहसील के श्रीनगर गांव का रहने वाला हूँ, मैं पिछले 30 वर्षों से पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ जिसमें पर्यावरण संरक्षण व जल संरक्षण, नदी संरक्षण आदि सम्मिलित है, मैं पिछले 10 साल से तरुण भारत संघ में जुड़ा हुआ हूँ, मैं विभिन्न विश्वविद्यालय कॉलेज स्कूलों में छात्रों को पर्यावरण व जल संरक्षण के लिए पिछले 25 वर्षों से रसायन विज्ञान व्याख्याता के रूप में जल संरक्षण के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, इस अभियान में लगभग 25000 छात्रों को फायदा मिला है, मैंने MSC Chemistry तथा B.Ed, पत्रकारिता जनसंचार, एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट, LLB कर रखा है, मैं वर्तमान में विश्व बाढ़ सुखाड़ आयोग के सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ तथा हाल ही में विश्व विद्या समिति के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया है, पहाड़ों के बीच में जगह-जगह डोल बनाकर जल को संचित कर रहे हैं, उन्होंने क्षेत्र में अनेकों स्थानों पर सभी के सहयोग से जलाशय बनाए हैं, जिसका उपयोग वन्य जीवों के लिए हो रहा है स्कूल व कॉलेज के तथा NSS व NCC के छात्रों के साथ व ग्रामीणों के साथ मिलकर गड्डे खोदकर जल का संचय कर रहे हैं, स्कूल व कॉलेज में छात्र-छात्राओं को जल बचाने का आह्वान कर व जल के महत्व को बता रहे,



पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं, जोहड व तालाबों की खुदाई कर रहे हैं तथा पुराने नदी व तालाबों को जगह-जगह अवकाश के रोज सभी छात्रों तथा ग्रामीणों के साथ मिलकर उन्हें साफ कर रहे हैं, जिससे जल संचित हो सके, औद्योगिक क्षेत्र में पाउडर से फैल रही बीमारी का मुआयना करने पहुंचे राजस्थान पर्यावरण बोर्ड के सदस्य, जिनके साथ पर्यावरण बचाओ समिति के अध्यक्ष नेहपाल सिंह ने पर्यावरण को होने वाली नुकसान के बारे में बताया, इस अवसर पर पर्यावरण समिति के सदस्य खुशवीर सिंह जोजावर, सिवान के विधायक हमीर सिंह भायल ने पर्यावरण प्रदूषण की पुष्टि सभी ग्रामीणों के सामने की, जिसमें नेहपाल सिंह का योगदान रहा।

राजस्थान पत्रिका अभियान के तहत जगह-जगह पौधे लगवा रहे हैं जिनके प्रमाण साथ में दिए हुए हैं, अलवर जिले में नेहपाल सिंह पत्रिका जनप्रहरी के रूप में कार्य कर रहे हैं। जिन्होंने प्रदूषण को रोकने के लिए पत्रिका कार्यालय में जल संकट का स्थाई समाधान करने की बात कही तथा उन्होंने प्रदूषण से हो रही बीमारियों के बारे में बताया। इन्होंने बांधों से अतिक्रमण को हटाया, भराव क्षेत्र से जल को बढ़ाया जिससे राजगढ़ क्षेत्र के बांधों में गत वर्षों से पानी का अधिक भराव हुआ है, पृथ्वी दिवस, जल संसाधन दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदूषण को रोकने अधिक से अधिक पेड़ लगाने व जल बचाओ करने के बारे में कई हजार छात्रों को प्रेरित कर रहे हैं। राजगढ़ शहर में भी जगह-जगह

भामाशाहों के साथ मिलकर पेड़ लगा रहे हैं, तथा तालाबों में जोहड़ों को और अधिक गहरा बनवा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण की स्कूल व कॉलेजों में छात्रों को शपथ दिला रहे हैं तथा प्लास्टिक को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के लिए छात्रों को शपथ दिला रहे हैं साथ ही उन्हें कपड़े के थैले को वितरित कर रहे हैं तथा कपड़े का थैला ही उपयोग में स्कूल में कॉलेज के छात्र ले रहे हैं। गंगा बाग के प्राचीन कुंड पर सफाई करके सभी लोगों के साथ क्षेत्र के पुराने कुण्ड को जल भराव के रूप में बनवाया है। विश्व ओजोन दिवस पर ग्रामीण व छात्रों को कम से कम एसी फ्रिज उपयोग करने की बात कह रहे हैं, क्योंकि इस प्रदूषण से फ्रीऑन के द्वारा ओजोन मंडल में छिद्र हो रहे हैं, नेहपाल सिंह प्रकृति को बचाने के लिए सभी समाचार पत्रों में संपादकीय लेख लिख रहे हैं। इसके प्रमाण संलग्न है आपने पत्रकारिता के माध्यम से रसायन विज्ञान व्याख्याता के माध्यम से कई वर्षों से पर्यावरण संरक्षण पर कार्य कर रहे हैं। भारत के जल पुरुष डॉ राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में तरुण भारत संघ से जुड़कर जगह-जगह जल बचाओ का कार्य कर रहे हैं, जिन्हें बाढ़ सुखाड़ आयोग, उदयपुर वाटर कांक्लेव के माध्यम से जल संरक्षण पर कार्य कर रहे हैं। वन्यजीवों के संरक्षण के लिए भी जगह-जगह जलाशय व पोखरणों पर कार्य कर रहे हैं तथा कई प्रदेशों में व्याख्याता रसायन विज्ञान व पर्यावरण विद् के रूप में व्याख्यान दे रहे हैं जिनके सहयोग से लोगों ने बहुत अधिक पेड़ लगाए हैं तथा पेड़ों को बचाव के लिए भी सब लोग पेड़ बचाओ अभियान भी चला रहे हैं।



राजगढ़. श्रीनगर बांटेन गांव के श्मशान घाट की भूमि पर पौधरोपण करते लोग।



मालाखेड़ा सीनियर स्कूल में पौधरोपण करते अध्यापक।



नीरज त्रिवेदी

ग्रामीण विकास विभाग, गया, बिहार



गया के तेलारी में अनूठे प्रयास ने बनाया पंचायत को खास

गंदे पानी के प्रबंधन की पहल से यह जल संरक्षण परियोजना तैयार हो गई। परियोजना के तहत नीमचक बथानी के ब्लॉक परिसर के पास 95 एकड़ तेलासी हिलॉक की वर्षा का उपयोग कर रहे हैं।

जल संरक्षण परियोजना, जो समुदायों के समर्थन से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपशिष्ट जल प्रबंधन से संबंधित है। इस परियोजना के तहत हम नीमचक बथानी के ब्लॉक परिसर के पास 95 एकड़ तेलासी हिलॉक की वर्षा का उपयोग कर रहे हैं।

बरसात के मौसम में या किसी अन्य दिन, तेलासी हिलॉक और आसपास के क्षेत्रों में होने वाली वर्षा जल का इष्टतम स्तर के साथ उपयोग किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत जलाशय में संग्रहित वर्षा और जल चैनल के माध्यम से जल संरक्षण टैंक में एकत्र किया जाता है। जल संरक्षण टैंक में बनाई गई रिचार्ज बोरवेल संरचना एक महीन जाली पाइप के माध्यम से प्रति घंटे 1.5 लाख लीटर पानी को निकालने की क्षमता रखती है, जो 93 फीट अंदर है, जो एक किलोमीटर के दायरे में जल स्तर को बेहतर बनाने में मदद करती है।

जल संरक्षण टैंक के किनारे पर चेक डैम बनाया गया है, जो इष्टतम पानी को संरक्षित करने में मदद करता है और बोरवेल संरचना के माध्यम से अधिकतम पानी निकालने के लिए बोरवेल को रिचार्ज करने में मदद करता है। परियोजना के

विभिन्न परिणामों का अध्ययन किया जा रहा है और इसे विस्तार देने की योजना पर काम जारी है। यह परियोजना ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वश्रेष्ठ

पूर्वी क्षेत्र श्रेणी में तेलारी पंचायत, गया जिले में चुनी गई और बिहार को तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड के तौर पर चुना गया।





निर्मल यादव

बावल गांव, बडगांव, झांसी, यूपी

जल संकट के लिए कुख्यात बुंदेलखंड इलाके में तालाब बना संकट मोचक



चार एकड़ में बने तालाब ने कुछ समय में न सिर्फ किसानों के लिए लाइफ लाइन का दर्जा पा लिया, सूखी, खराब जमीन का बदनुमा दाग भी धो दिया।

यूपी में झांसी जिले के बावल गांव में ऊसर बंजर जमीन के लिए एक तालाब वरदान साबित हो रहा है। गाँव की जिस जमीन को पानी की उपलब्धता के लिहाज से सरकारी रिकॉर्ड में ड्राई लैंड, ब्लैक बाल्ट जैसे तमगे दिए गए, उस जमीन पर साल 2021 में बने महज एक तालाब ने किसानों को साल भर का पानी उपलब्ध करवा दिया। पहले जिस जमीन पर साल में किसान सिर्फ एक फसल ले पाते थे, अब वही जमीन महज एक तालाब की बदौलत साल भर हरी भरी रहती है, जिससे किसान अब तीन फसलें ले रहे हैं।

ड्राई लैंड से पहली बार 2021 में उपजी धान की फसल।

दिल्ली और जर्मनी में दो दशक तक पत्रकारिता करने के बाद कोरोना काल में अपने गाँव लौट कर खेती को अपनाने वाले पत्रकार निर्मल यादव ने प्रकृति के साथ तालमेल कायम करने वाली खेती के प्रकल्प को आगे बढ़ाया। इस क्रम में उन्होंने अपने ऊसर खेत को तालाब की मदद से उपजाऊ बनाने के लिए इंटिग्रेटेड फार्मिंग का सफल मॉडल बनाने के उपाय किए। पिछले पाँच



साल से चल रहे इस प्रकल्प की सबसे बड़ी उपलब्धि नितांत विपरीत परिस्थितियों में बनाया गया तालाब है। जिसे सृजन सरोवर नाम दिया गया है। इस इलाके में सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद किसान तालाब बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बावल गांव में बना ये तालाब अब किसानों को जलसंकट का स्थायी समाधान मुहैया करा रहा है, साथ ही सरकारी अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक भी इस तालाब को पानी का पुरोधा बताकर किसानों को प्रेरित करते हैं।

बहुउद्देशीय हो चुके इस तालाब के

महत्व को अब किसान समझ रहे हैं।

इससे न केवल साल भर सिंचाई के लिए पानी मिलता है, बल्कि यह मछली पालन से अतिरिक्त आय का भी स्रोत है। भूजल की तुलना में तालाब के पानी से सिंचाई करने पर उपज भी ज्यादा मिलती है, साथ ही आसपास के कुआँ और बोरवेल का जलस्तर भी अब बढ़ने से इनमें पानी साल भर रहने लगा है। लगभग चार एकड़ के इस खेत में पहले एक भी पेड़ नहीं था, तालाब बनने से खेत में अब लगभग सौ फलदार दरख्त अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। पूरे खेत की ग्रीन चार दिवारी तालाब की बदौलत ही मुमकिन हो सकी है। अमरूद, आम, संतरा, मुसम्मी, नीबू, करौंदा और ऐपल बेर जैसे फल अब इस खेत की उपज की फेहरिस्त में शामिल हो गए हैं। महज एक तालाब की बदौलत ये खेत कार्बन क्रेडिट से भी अब कमाई करने के लिए तैयार है। ये खेत अब तमाम तरह के परिंदों का घरौंदा बन कर कुदरत के अनूठे रंगों से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन गया है। साथ ही सृजन सरोवर अब आसपास के खेतों से जुड़े दर्जन भर से ज्यादा किसानों के लिए लाइफलाइन बन गया है।



पुनीत खन्ना, हिना खन्ना

संकल्प वेलफेयर सोसाइटी, जालंधर, पंजाब

पंजाब की धरती पर जल संरक्षण, संवर्धन के लिए जरूरी हैं ऐसे अभियान



पंजाब में जल संकट किसी से छिपा नहीं है। सरकारी, गैरसरकारी प्रयासों में एक प्रयास है पुनीत खन्ना का; जालंधर के पुनीत जल संकट न आए इस अभियान के चलते बन रहे हैं जल प्रहरी.....

ग्रामीण इलाकों में जमीन पर तालाब खुदाई, नहर खुदाई कर जल संरक्षण, संवर्धन के काम चल रहे हैं लेकिन शहरों में जरूरी है कि जल संरक्षण, इस्तेमाल किए पानी का दोबारा इस्तेमाल हो व पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया यह जागरूकता है जरूरी..... पंजाब के जालंधर जिले में संकल्प वेलफेयर सोसाइटी ने इस अभियान का शुभारंभ पिछले 10 वर्ष पूर्व किया। तब से आज तक जल एवं पर्यावरण संरक्षण का कार्य निरंतर जारी है। जालंधर, पंजाब से प्रारंभ होकर यह अभियान आज पंजाब के विभिन्न जिलों में जन-जागृति का स्वरूप ले चुका है। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु सैकड़ों विद्यालयों, कॉलेजों, ग्राम पंचायतों एवं सोसाइटीज में 'सेमिनार एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम' आयोजित किए गए हैं वहीं पिछले वर्षों में संस्था द्वारा 'एक लाख से अधिक वृक्षारोपण' किया जा चुका है।

संस्था द्वारा घर-घर तक पहुंचाया जा रहा है संदेश.....

नलों को खुला न छोड़ें और जल की हर बूंद



बचाएं।

वर्षा जल को रेनवाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से संचित करें।

घर से निकलने वाले जल का पुनः उपयोग (रिसाइकल) कर जल-संरक्षण में योगदान दें।

इन प्रयासों से अब तक सैकड़ों परिवार जुड़े हैं। साथ ही 'जलाशयों की सफाई एवं पुनर्जीवन' के कार्यों में भी संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त 'कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में भी

निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हजारों कपड़े के थैले बनाकर वितरित किए गए हैं ताकि प्लास्टिक-मुक्त समाज की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके।

संस्था का संकल्प है कि

प्रत्येक वर्ष कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएंगे, अपने घर से जल का संरक्षण करेंगे, जल स्रोतों को स्वच्छ रखेंगे एवं कचरे का उचित प्रबंधन कर पर्यावरण को संतुलित बनाए रखेंगे।



राजेश कुमार शुक्ला

वाराणसी



बनारस के घाट पर समर्पित एक शख्सियत की दिनचर्या है मां गंगा की सेवा

क्या नदी, तालाब, कुएं में गंदगी देखकर मन व्यथित होता है। होता है तो क्या उसकी सफाई के प्रयास आपने किए। एक शख्स हैं जो गंगाजल से साफ करते हैं गंदगी।

वर्ष 2014 में जब मां गंगा के तट और गंगाजल की तलहटी में फैली गंदगी ने मन को व्यथित किया, तब मैंने बिना किसी आर्थिक सहायता के, अपने तन, मन और धन से 'गंगा सफाई अभियान' प्रारंभ किया। उस दिन से लेकर आज तक फिर चाहें तपती गर्मी हो, सर्दी हो, वर्षा या गंगा की बाढ़ में निरंतर 'गंगाजल की सफाई, आरती और जनजागरण कार्य' में जुटा हूं। हर दिन गंगा तलहटी की सफाई करने के साथ-साथ, लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों से गंगाजल में गंदगी न करने की अपील भी की करते हैं।

चूँकि पूरे देश भर से लोग काशी पहुंचते हैं और मां गंगा की आरती, काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। एक अपील है कि मां गंगा के तट प्लास्टिक बैग न लाएं, न ही अक्षत, पूजन सामग्री डालकर मां गंगा को गंदा करें। राजेश केवल गंगा तट ही नहीं, बल्कि 'काशी के पौराणिक कुंडों और तालाबों' की स्वच्छता के लिए भी लगातार अभियान चला रहे हैं; इस सतत प्रयास का परिणाम यह है कि आज वाराणसी के घाट पहले से कहीं अधिक स्वच्छ, सुंदर और श्रद्धास्पद दिखाई देते हैं।

पिछले 11 वर्षों से जारी इस निस्वार्थ सेवा से प्रेरित होकर लाखों लोग 'स्वच्छता और जल



संरक्षण' के प्रति जागरूक हुए हैं। इसीलिए इन प्रयासों को समय-समय पर 'राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मीडिया' ने सराहा और प्रकाशित किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मेरे कार्यों की प्रशंसा अपने ट्विटर पर की है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी' द्वारा 'गंगाजल सेवा' हेतु सम्मान प्राप्त

हुआ है।

जल शक्ति मंत्रालय (राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन) द्वारा गंगा का हीरो कहकर सम्मानित किया गया।

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने भी गंगा सफाई के कार्यों को सराहा और सम्मानित किया।



प्रार्थना

जो मां गंगा हम सबके काम आती हैं, यदि हम उनके काम आ सकें, तो वही सबसे बड़ा सम्मान है। नमामि गंगे रूपी इस 'सांस्कृतिक महायज्ञ' में मेरा प्रयास लगातार जारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी निर्मल और अविचल गंगा का आशीर्वाद पा सकें। 'मुझे प्राप्त 'जल प्रहरी सम्मान' न केवल मेरा उत्साह बढ़ाएगा, बल्कि देशभर के अन्य जलप्रहरियों को भी प्रेरित करेगा कि वे जल संरक्षण और नदी संरक्षण के लिए आगे आएँ।'



रामेश्वर लाल मीणा

मोचा का पुरा, वजीरपुर, सवाई माधोपुर, राजस्थान

मोचा का पुरा गांव में जलस्रोत पुनर्जीवन: एक सफल सामुदायिक पहल



तीन तालाब, तीनों सूख गए, लोगों ने कब्जा कर लिया। नहर से पानी लाए लेकिन लाने का रास्ता नहीं दिया, फिर भी तकनीक, मेहनत योजना से सवाई माधोपुर का मोचा का पुरा गाँव, पानीदार है

मोचा का पुरा गाँव कभी तीन प्राकृतिक जलस्रोतों से घिरा हुआ था। समय के साथ अनियोजित भूमि उपयोग और अतिक्रमण के कारण ये तीनों ही जलस्रोत नष्ट हो गए। पहले जलस्रोत को किसान द्वारा अतिक्रमण कर खेती योग्य भूमि में बदल दिया गया। दूसरे जलस्रोत को स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भर दिया गया और उसके ऊपर उच्च माध्यमिक विद्यालय का निर्माण कर दिया गया। तीसरा जलस्रोत जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण था, पिछले 20 वर्षों में अपने कैचमेंट क्षेत्र पर अतिक्रमण और उसे खेती में बदल देने के कारण पूरी तरह सूख गया।

गांव पर प्रभाव...

इन जलस्रोतों के नष्ट होने से गाँव में गंभीर जल-संकट उत्पन्न हो गया। जहाँ कभी भूजल स्तर 50 से 100 फीट था, वह गिरकर 600 से 700 फीट तक पहुँच गया। सभी परंपरागत कुएं सूख गए और किसानों को पीने व सिंचाई दोनों के लिए गहरे बोरवेल खोदने पड़े। बोरवेल का पानी अत्यधिक कठोर था जिसमें 'फ्लोराइड और अन्य खनिजों की मात्रा बहुत अधिक' पाई गई, जिससे पानी पीना मुश्किल हो गया।



ग्राम समिति का गठन...

इस विकट स्थिति से निपटने के लिए वर्ष 2020 में गांव के पेशेवरों और ग्रामीणों ने मिलकर एक समिति बनाई।

ग्रामीण जन कल्याण विकास समिति, मोचा का पुरा

समिति ने गांव के जलस्रोतों को पुनर्जीवित करने, विशेषकर तीसरे सूखे जलस्रोत को पुनः जीवित करने का संकल्प लिया। पुनर्जीवन की रणनीति बनी कि गांव से लगभग 1.5 किमी दूर एक

परित्यक्त कृत्रिम नहर प्रणाली मौजूद थी, जिसमें बरसात के दिनों में अब भी पानी बहता था। समिति ने इसे सूखे जलस्रोत को भरने के लिए एक उपयुक्त स्रोत के रूप में पहचाना। लेकिन इस पानी को तालाब तक पहुँचाने के लिए किसानों की जमीनों से होकर चैनल बनाना पड़ता, जिसे किसी भी किसान ने स्वीकार नहीं किया।

नवीन समाधान: भूमिगत पाइपलाइन
भूमि विवाद से बचने के लिए समिति अध्यक्ष ने एक 'भूमिगत पाइपलाइन' के माध्यम से नहर प्रणाली को जलस्रोत से जोड़ने का प्रस्ताव रखा।

एक विस्तृत पुनर्जीवन परियोजना तैयार की गई और उद्योगों व व्यक्तियों से दान लेकर पर्याप्त धन एकत्र होने के बाद 'सिर्फ एक वर्ष में' पाइपलाइन का कार्य पूरा कर लिया गया। **हरित अभियान:** इसके साथ ही गांव में बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान शुरू किया गया। मां के नाम एक पेड़... अभियान ने न केवल पर्यावरण को सुधारने में मदद की, बल्कि पूरे गांव को एकजुट भी किया। **दो वर्षों के परिणाम:** यह परियोजना मोछा का पुरा के लिए परिवर्तनकारी साबित हुई है। बरसात के मौसम में पानी अब 'नियमित रूप से पाइपलाइन द्वारा जलस्रोत में पहुंच रहा है। गांव का भूजल स्तर लगातार बढ़ रहा है। कई पुराने, सूखे कुएं' फिर से जीवित हो गए हैं। बोरवेल में अब पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है और उसमें खनिजों की मात्रा 'काफी कम' हो गई है। पीने के पानी की गुणवत्ता और सिंचाई सुविधा दोनों में सुधार हुआ है।



Rizwan Basha Shaik

IAS, District Collector, Jangaon



“Mana Jilla – Mana Neellu” (Our District – Our Water) low-cost water conservation model

“Mana Jilla – Mana Neellu” (Our District – Our Water), launched and government employees across all departments voluntarily contributed from their own pockets to construct 7,175 rainwater harvesting pits within just 20 days.

Under the campaign “**Mana Jilla – Mana Neellu**” (Our District – Our Water), launched on July 5, government employees across all departments voluntarily contributed from their own pockets to construct **7,175 rainwater harvesting pits** within just **20 days**. The initial target was 5,000 pits; however, with enthusiastic participation from every government department, the target was far exceeded.

Each pit—measuring **1m x 1m x 1m** and costing just **₹1,500**—is capable of storing around **1,000 litres** of water. Stones and soil for the pits were sourced locally by gram panchayats from demolished structures or available material, ensuring that the project remained sustainable and cost-effective.



The initiative is estimated to contribute **at least one TMC of water**, helping recharge groundwater levels across the district. Indeed, the **average groundwater depth** improved remarkably—from **10.21 meters in April 2025** to **4.84 meters in January 2022**, reflecting the positive long-term impact of such efforts.

The **National Water Mission**

(NWM), Ministry of Jal Shakti, Government of India, lauded the initiative as a “**people-driven, low-cost water conservation model**”, emphasizing that “every drop counts and every department can make a difference.” NWM Director **Dr. Archana Varma** personally commended the Jangaon district administration for this collective and voluntary effort.

District Collector **Rizwan Basha Shaik** emphasized that the vision behind the campaign was to ensure every household and institution in Jangaon has a rainwater harvesting pit, contributing to the district's sustainable water management. Through resource recycling, community participation, and bulk material mobilization, this campaign not only transformed groundwater prospects but also set an example for other districts across India.



Sabyesachi Bharti

Centre for Media Studies, Deputy Director



Centre for Media Studies, Deputy Director

These sessions sensitised them to the urgent need for mainstreaming wetland and water issues in media narratives, and encouraged a deeper understanding of traditional water systems and their role in climate resilience.

Launched on World Wetlands Day 2024 at Sirpur Wetland, Indore, by Shri Mohan Yadav, Hon'ble Chief Minister of Madhya Pradesh, and Dr. Musonda Mumba, Secretary General of the Ramsar Convention, Wetlands for LiFE is part of the "Wetlands Management for Biodiversity and Climate Protection" project, supported by GIZ, BMUV, and IKI, and implemented in collaboration with the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC).

Aligned with the Hon'ble Prime Minister's call for "Jan Shakti se Jal Shakti", the initiative engaged citizens across eight cities—New Delhi, Patna, Bhubaneswar, Bhopal, Indore, Shimla, Srinagar, and Lucknow—to promote water stewardship and wetland rejuvenation.

A key focus was youth capacity building:

- **336 postgraduate media students** were trained as environmental journalists.

- **168 youth communicators** learned mobile-based storytelling to document community-led conservation.

- **469 youth registered as Wetland Mitras**, volunteering for wetland monitoring, awareness drives, and eco-friendly actions.

The initiative engaged **5,555 participants** directly and reached 63,000+ citizens online, creating a strong public discourse on wetland conservation.

By combining education, participation, and storytelling, CMS VATAVARAN's Wetlands for LiFE has built a generation of informed Jal

Praharis—youth committed to protecting India's wetlands and reviving traditional water wisdom for a **जल आत्मनिर्भर भारत 2047**.

A key success of the initiative was the voluntary registration of 469 youth as Wetland Mitras. These Wetland Mitras took on-ground responsibility for identifying, monitoring, and protecting local wetlands.

They organised awareness drives in schools and colleges, documented seasonal changes in water bodies, and promoted eco-sensitive behaviours like waste reduction, native plantation, and rainwater harvesting.

Many also worked in close collaboration with local panchayats, school teachers, and NGOs to strengthen community-led conser-

vation efforts. To ensure the initiative was embedded in wider public discourse, 120 senior journalists and editors from across the country were engaged through focused consultations.

These sessions sensitised them to the urgent need for mainstreaming wetland and water issues in media narratives, and encouraged a deeper understanding of traditional water systems and their role in climate resilience.

In total, the initiative directly engaged 5,555 participants through workshops, knowledge

events, panel discussions, and field-based activities. The campaign's digital outreach extended to 63,000+ citizens, amplifying the importance of wetland conservation and youth involvement across online platforms.

Importantly, the initiative demonstrated a replicable model of combining education, participation, and storytelling to transform passive awareness into active stewardship.

From students who had never visited a wetland before, to youth who returned home to revive vil-

lage ponds and stepwells, the campaign ignited a sense of environmental responsibility and pride in one's natural heritage.

Beyond numbers, Wetlands for LiFE is a testimony to what becomes possible when institutions, government agencies, and citizens come together with a shared vision.

It is a living example of how youth can be powerful catalysts in protecting and restoring water ecosystems—using both traditional wisdom and modern communication tools.



भोज कुमार साहू

राजनंदगांव, छत्तीसगढ़



जल बचाओ अभियान, डोंगरगांव के प्रयासों हर दिन तय कर रहा है सुखद सफर

इस अभियान ने जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया भू-जल स्तर में बढ़ोतरी की अस्पताल एवं नगर की जल किल्लत दूर की पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया।

राजनंदगांव जिले के डोंगरगांव नगर तथा आसपास के क्षेत्रों में जल संरक्षण को लेकर एक व्यापक 'जन-जागरूकता आधारित 'जल बचाओ अभियान' पिछले 'विगत 14 वर्षों (2011 से निरंतर)' से सक्रिय रूप से संचालित किया जा रहा है। इस अभियान ने न केवल जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया है, बल्कि लोगों के विचारों और व्यवहार में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया है। डोंगरगांव नगर में करीबन 30 बंद पड़े कुओं को पुनर्जीवित कर जल उपयोग में लाए। इन 'लगभग' 30 बंद पड़े कुओं की सफाई, गहरीकरण, रंग-रोगन एवं मरम्मत जनसहयोग से करवाई गई। जागरूकता के कारण ग्रामीणों ने इन कुओं को दोबारा उपयोग में लेना शुरू किया, जिससे पेयजल उपलब्धता में सुधार हुआ।

'सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगांव में जल संकट का समाधान'

डोंगरगांव में पहले बोर का पानी 'मुश्किल से 10 मिनट' तक ही उपलब्ध होता था। समाधान के रूप में बिल्डिंग की पूरी पाइपलाइन को वाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम से जोड़ा; इस सिस्टम का 'निर्माण जनसहयोग से' किया गया।

परिणाम स्वरूप आज वही बोर 3 से 4 घंटे



तक लगातार पानी दे रहा है', जो अस्पताल में बड़ी राहत साबित हुआ।

बोरिंग के आसपास सोखतों का निर्माण
भू-जल रिचार्ज बढ़ाने के लिए बोरवेल के आसपास 'सोखता गड्ढे' तैयार किए गए, जिससे वर्षा जल सीधे भूमि में समाहित होने लगा।

नदी-नालों की सफाई और पुनर्जीवन
राजनंदगांव एवं बालोद जिले में लगभग '10 नदियों/धनालों' की सफाई की गई।

विसर्जन के बाद नदी-तालाबों में जमा

कूड़ा-करकट, मूर्तियां, 'मलबा तथा अन्य सामग्री, निकालकर जल स्रोतों को स्वच्छ बनाया गया। खुले, टपकते नलों में टोटी लगवाना जल व्यर्थ न हो, इसके लिए मोहल्लों और सार्वजनिक स्थानों के 'खुले नलों में टोटियां' लगवाई गईं, जिससे अनावश्यक जल बहाव लगभग बंद हो गया।

जल संरक्षण के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान

निरंतर रूप से बैनर, पोस्टर, रैली, नुक्कड़



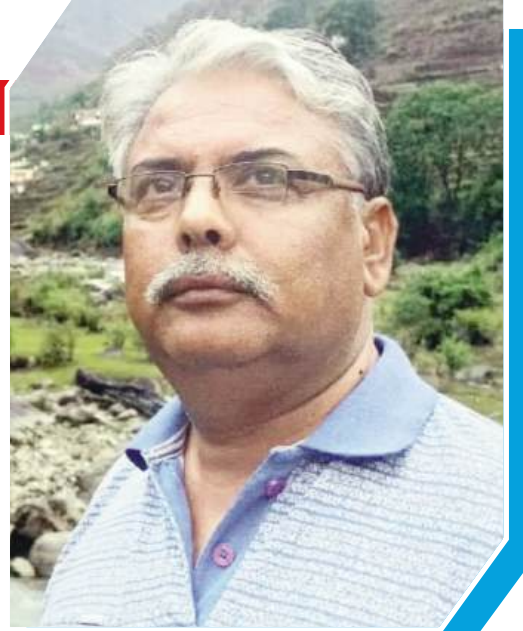
नाटक, ग्राम, स्तर पर बैठकों के माध्यम से पानी बचाने का संदेश दिया गया।

स्कूल-कॉलेजों में कार्यक्रम

विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए संगोष्ठियां, चित्रकला प्रतियोगिताएं, पोस्टर निर्माण, जल बचाओ, जल जीवन' थीम पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं। पौधों की सिंचाई ड्रिप इरीगेशन से करवाने के लिए प्रेरित किया। पानी की बचत के लिए पौधों को टपक सिंचाई प्रणाली से सींचा गया, जिससे कम पानी में बेहतर परिणाम मिले। पशु-पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था की गर्मी के कठिन दिनों में पशुओं और पक्षियों के लिए 'दानाहपानी' की व्यवस्था की गई। यह पहल पर्यावरण एवं संवेदनशीलता का सुंदर उदाहरण है।

संजय राणा

बडौत, बागपत, उप्र, एनवार्नमेंट एंड सोशल रिसर्च ऑर्गनाइजेशन एगो के निदेशक, दिल्ली पुलिस के पूर्व अधिकारी



वर्दी के साथ भी, वर्दी के बाद भी सुरक्षा को समर्पित एक जल प्रहरी

पांच राज्यों के 300 से अधिक विद्यालयों में हजारों विद्यार्थियों को जल संरक्षण, स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन, नैतिक मूल्यों एवं जिम्मेदार नागरिकता की शिक्षा देते हुए यह कारवां जारी है...

संजय राणा, उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के निवासी एवं दिल्ली पुलिस के पूर्व अधिकारी हैं, जिन्होंने वर्ष 2019 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण को अपना जीवन उद्देश्य बनाया। उन्होंने 'आओ नदियों को जानें' और 'जलवायु परिवर्तन समझें' जैसे विषयों को लोकचर्चा में लाने का संकल्प लिया। उनके नेतृत्व में वर्ष 2009 से चल रही 'व्यवहार परिवर्तन यात्रा' एक अभिनव सामाजिक, शैक्षिक अभियान के रूप में स्थापित हुई है। यह यात्रा संवाद, खेल, नाटक, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला एवं समूह गतिविधियों के माध्यम से छात्रों, युवाओं और शिक्षकों में पर्यावरणीय संवेदनशीलता और नागरिक जिम्मेदारी का भाव जागृत करती है। वर्ष 2025 तक इस यात्रा ने पांच राज्यों के 300 से अधिक विद्यालयों में हजारों विद्यार्थियों को जल संरक्षण, स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन, नैतिक मूल्यों एवं जिम्मेदार नागरिकता की शिक्षा दी।

बागपत और मेरठ क्षेत्रों में विद्यालय परिसरों, सार्वजनिक स्थलों और मुक्तिधामों में 5,000 से अधिक वृक्षारोपण किए, जिनकी देखरेख स्थानीय समुदाय स्वयं कर रहे हैं। उन्होंने वृक्षारोपण को केवल प्रतीकात्मक क्रिया न





मानकर 'जीवंत पर्यावरण शिक्षा' का माध्यम बनाया। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत-पहल के अंतर्गत उन्होंने ग्रामीण व शहरी महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म स्वच्छता, पोषण एवं स्वच्छ जल उपयोग के प्रति जागरूक किया। इस पहल ने महिलाओं में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास किया।

वर्ष 2019 में आयोजित 'बा बापू 150 यात्रा' से अहिंसा, स्वावलंबन, नारी सम्मान और प्रकृति प्रेम को विद्यालयों एवं समुदायों में पुनर्जीवित किया। इसी क्रम में 'कैलेंडर बनाओ अभियान' द्वारा बच्चों को पर्यावरणीय रचनात्मकता से जोड़कर बाल चेतना को नया आयाम दिया।

संजय राणा का दृष्टिकोण: व्यावहारिक, सहभागितापूर्ण और अनुभवात्मक है। उन्होंने दिल्ली, एनसीआर क्षेत्र में इग्नू के बीएसडब्ल्यू व एमएसडब्ल्यू के विद्यार्थियों को कचरा प्रबंधन, स्वच्छता और सामाजिक सर्वेक्षणों के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया, जिससे उन्हें वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों का अनुभव हुआ।

वर्ष 2024-2025 में उनकी हिमालयी यात्राएं जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का सशक्त माध्यम बनीं। इन यात्राओं के माध्यम से युवाओं को ग्लेशियरों के पिघलने, जैव विविधता के संकट और स्थानीय समुदायों के अनुकूलन प्रयासों से अवगत कराया गया।

सोनाक्षी श्री

कृमको, ग्रामिण विकास ट्रस्ट, कृमको भवन, ए-10, सेक्टर-1, नोएडा, उप्र

जल सुरक्षा और सतत विकास की एक जन सहयोग के साथ जनोपयोगी पहल



कृमको के सामाजिक विकास प्रकोष्ठ ग्रामीण विकास ट्रस्ट ने भारत में बढ़ते जल संकट, विशेष रूप से ग्रामीण और सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में, समाधान हेतु जल क्रांति अभियान शुरू किया कई राज्यों में परिणाम ला रहा है।

कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृमको) के सामाजिक विकास प्रकोष्ठ ग्रामीण विकास ट्रस्ट ने भारत में बढ़ते जल संकट, विशेष रूप से ग्रामीण और सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में, समाधान हेतु 'जल क्रांति' अभियान की शुरुआत की। यह पहल 'जल जीवन मिशन', 'स्वच्छ भारत अभियान' तथा 'जल शक्ति अभियान' के उद्देश्यों के अनुरूप जल संरक्षण, संचयन, पुनर्चक्रण और जन-जागरूकता पर केंद्रित है। यह अभियान बीते दो दशकों में देश के '24 राज्यों' में फैला है, जिसमें 'गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, असम' और 'जम्मू-कश्मीर' जैसे जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में वर्ष 2017-18 से गंभीरता से काम कर रहा है। जल क्रांति ने 'पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीकों को जोड़कर समुदाय आधारित टिकाऊ जल समाधान प्रस्तुत किए हैं।

मुख्य उपलब्धियां...

जलाशय पुनर्जीवन: 100 से अधिक तालाबों का पुनर्निर्माण (105 एकड़ क्षेत्र), जिससे लगभग 10 मिलियन घन मीटर भूजल पुनर्भरण हुआ। **वर्षा जल संचयन:** सिक्किम के विद्यालयों व आंगनवाड़ियों में वर्षा जल संचयन



इकाइयां स्थापित कर '17,000 ग्रामीणों और '100 से अधिक विद्यार्थियों' को लाभ। **सिंचाई व जलवृद्धि:** 44 चेकडैम, 21 फार्म पॉन्ड और 360 हेक्टेयर में बंधान निर्माण द्वारा 4.5 लाख घन मीटर वर्षा जल का संरक्षण, जिससे '2,500 परिवार' लाभान्वित हुए।

तकनीकी इनोवेशन: गुजरात के रुखाड़ी गाँव में सौर ऊर्जा चालित कुएं से '2,000 ग्रामीणों' को पेयजल व '25 एकड़ भूमि' को सिंचाई सुविधा प्राप्त हुई। **क्षमता निर्माण:** जल जीवन मिशन के तहत 4 राज्यों में क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में 7 लाख ग्रामीणों तक

पहुंच, 150 से अधिक जागरूकता अभियानों और जल समूहों, छात्र क्लबों एवं स्वयं सहायता समूहों का गठन। प्रभाव-इस पहल से 9.5 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष लाभ हुआ, 73 करोड़ लीटर जल संचयन, 30 फीसद तक फसल उत्पादकता वृद्धि हुई तथा 15 प्रतिशत पारिवारिक आय में वृद्धि दर्ज की गई। ग्रामीण विकास ट्रस्ट की जल क्रांति एक सामुदायिक, नवाचार आधारित और टिकाऊ जल प्रबंधन मॉडल है, जो भारत के जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों को आत्मनिर्भर, समृद्ध और जल-सुरक्षित समाज में बदलने की दिशा में अग्रसर है।



सोनू गहलोत

उज्जैन, मध्य प्रदेश



मेहनत, योजना के पसीने से पुनर्जीवित हुई शिप्रा, चंद्रभागा और विष्णु सागर

शिप्रा नदी को पुनः प्रवाहमान बनाने के लिए नदी की सहायक नदियों का चयन किया गया। करीबन 22 ऐसी सहायक नदियां चिन्हित की गईं उसमें से सर्वप्रथम चंद्रभागा नदी पर कार्य प्रारंभ किया गया। लगभग 10 किलोमीटर लंबी इस नदी को गहरा, चौड़ा कर पुनर्जीवित किया।

उज्जैन में किसानों ने अपने संसाधन लगाकर नदी से निकली मिट्टी को अपने खेतों पर डाला। जगह-जगह पर कच्चे स्टाफ डैम छोड़े गए ताकि वर्षा का जल संचय हो सके। बरसात समाप्त होने के चार माह बाद तक इसमें पानी रहता है। आसपास का ना सिर्फ ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ बल्कि आसपास पौधारोपण के बाद एक इको सिस्टम भी डेवलप हुआ। बाकी अन्य नदियों पर कार्य लगातार जा जारी है।

विष्णु सागर...

अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे प्राचीन सप्त सागरों में से एक विष्णु सागर में शहर के हजारों हाथ जुटे तो लुप्त होते इस तालाब में पानी, पक्षी और पर्यावरण की रौनक लौट आई। आसपास क्षेत्र में राम जनार्दन मंदिर के समीप स्थित इस तालाब को करीब पांच हजार लोगों ने पसीने से सींचा है। आज करीब 2 हेक्टेयर का यह तालाब पानी और हरियाली से लबालब है।

कैसे हुआ बदलाव:

विष्णु सागर विकास समिति ने इसे संवर्धन का काम हाथ में लिया। तीन स्तर पर योजना बनाई,

सफाई, गहरीकरण, पथरीकरण तथा हरियाली। करीबन 55 संस्थाओं के 6 हजार से ज्यादा लोगों ने श्रमदान कर करीब 2000 ट्रॉली मिट्टी निकाली। हरियाली अभियान शुरू हुआ तब से सभी संस्थाओं के सहयोग और 2500 पौधे रोपे जाने से तालाब के आसपास हरियाली दिख रही है। विष्णु सागर क्षेत्र के सभी साधक इसे अपनी तपोभूमि मानते हैं। उनकी प्रेरणा से तालाब संरक्षण के लिए कई माह तक चली मेहनत सफल हुई। सबसे बड़ी बात, इस श्रमदान में बच्चों का विशेष योगदान रहा। एकलव्य समूह ने भी जल कलश यात्रा निकाली और परिणाम सबके सामने हैं।

नकवर गंगा और चंद्रभागा पर कार्य शुरू हुआ

असंख्य मां के गर्भ सी नदियां अपना मूल अस्तित्व खो चुकी हैं, जिनका अमरत्व खत्म हो चुका था, जो दशकों से नाला बनकर बह रही थीं। फिर किसी ने सोचा नहीं कि नकवर गंगा और चंद्रभागा ये दो नदियां जिनके पुनर्जीवन के प्रयासों के फल अब साफ दिखाई दे रहे हैं। सात-आठ

किलोमीटर ऊपरी सड़क से लेकर अब तक बीस किमी दूरी तक ये दोनों नदियां जीवित हो गई हैं। अगर सब कुछ इसी तरह होता रहा तो अगला सिंहस्थ, श्रीमहाकाल की शिप्रा नदी का स्नेह इन नदियों के लिए भी अमर रहेगा।

जनसहयोग से चंद्रभागा को पुनर्जीवित किया:

शिप्रा नदी के कोमडी तहसील क्षेत्र में लगभग 22 सहायक नदियां थीं जो इसे सालभर प्रवाहमान रखती थीं। लेकिन धीरे-धीरे इनमें से कुछ शिप्रा में मिलने वाली सूख गईं और शिप्रा को कुछ सत्रों में नाला बनकर बह रही। नर्मदा-शिप्रा लिंक होने के बाद भी विलक्षण रूप से यहां से बहाव घट गया। हालांकि सिंहस्थ 2016 के बाद शिप्रा पुनर्जीवन के लिए कई प्रयास किए गए। तब एक उत्साही युवा संघ द्वारा नकवर गंगा नामक 8 किमी लंबी नाला नुमा सहायक नदी को भी सजग किया गया।

जनसहयोग से नदी के सहायक संगम पर कार्य शुरू हुआ। चंद्रभागा नदी के उस सहायक संगम पर आज भी पानी बह रहा है। लेआउट के पास एक जगह पर शिप्रा नदी के, जल-प्रवाह को

रोकने के लिए अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। अब एक टीम इस पर बेहतर काम कर रही है।

सहयोग समिति का मानना है कि जल संरक्षण के कार्यों में यह पहला कदम किसी भी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए जरूरी है। नकवर गंगा और चंद्रभागा का संगम स्थल अब प्रवाहमान बना हुआ है। एक प्रयास कि अगला सिंहस्थ शिप्रा नदी के जल से ही हो।

‘शिप्रा से मिलेंगी चंद्रभागा’

शिप्रा को प्रवाहमान बनाए रखने के लिए उसके सहायक नदियों को भी पुनर्जीवित करना जरूरी है। इसके लिए जल संरक्षण का काम शुरू किया गया। नकवर गंगा नदी से शुरू हुआ काम आज आठ किमी लंबी सहायक नदी में बह रहा है। नदी में गर्मी के मौसम में भी पानी नहीं रुका। एक डेढ़ किमी तक जहाँ से यह नदी निकलती है वहाँ पर भी शिप्रा नदी के जल से मिलने वाली नदी आज भी प्रवाहमान है। सहायक नदियां बंद होने से शिप्रा का जल प्रवाह कम हो गया। लौटाने का सिर्फ एक तरीका है, सहायक नदियों को जोड़ना और प्रवाह को पुनर्जीवित करना। यह रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ पुरानी व्यवस्था है। नदी मिलन से शिप्रा जलमय होगी। चंद्रभागा नदी को पुनर्जीवित होता देख यह विश्वास पूरा हो रहा है।



समय के साथ ऐसे बदलता गया चंद्रभागा नदी का भाग्य



नदी की दशा बदलने के लिए लोगों ने किया काम।



वर्ष 2022 में ऐसी थी।



गौतम कुमार सिंह

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, पटना क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार



जैसे जैसे बढ़ता गया जल संग्रहण, चेहरों पर आत गई मुस्कान

जिले में 20 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में जल ग्रहण परियोजनाओं के सफल होने के बाद ग्रामीण के जीवन आए सही बदलाव...

देश में जल संरक्षण, जलग्रहण प्रबंधन और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। नाबार्ड में जिला विकास प्रबंधक, बिहार के रूप में कार्य करते हुए, 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले जलग्रहण परियोजनाओं का सफल संचालन आसान नहीं था। इससे न सिर्फ हजारों ग्रामीण परिवारों के जीवन में स्थायी परिवर्तन आया उनके चेहरे की मुस्कान ने आर्थिक तरक्की के भी रास्ते खोल दिए।

भोपाल (मध्य प्रदेश) में उपमहाप्रबंधक तथा रांची (झारखंड) में महाप्रबंधक के रूप में, उन्होंने जलग्रहण कार्यक्रमों को विस्तार देते हुए परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया।

उनके प्रयास केवल परियोजना प्रबंधन तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने क्षमता निर्माण, स्थानीय साझेदार संस्थाओं को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन एवं सतत सहयोग देकर आत्मनिर्भर बनाया।

निरंतर निगरानी एवं मूल्यांकन: परियोजनाओं की प्रगति का डेटा-आधारित मूल्यांकन कर सुधारात्मक कदम सुनिश्चित किए।

सहभागिता एवं समन्वय: सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों एवं समुदायों के



बीच सहयोग की सशक्त प्रणाली विकसित की।

सामुदायिक विश्वास निर्माण: स्थानीय नेतृत्व एवं प्रमुख जनमत धारकों के माध्यम से समुदायों में विश्वास और सहभागिता को प्रोत्साहित किया।

बिहार (मुंगेर) में दो परियोजनाएं तथा 'झारखंड' में '25 परियोजनाएं' सफलतापूर्वक पूर्ण की गईं, जिनसे जल संरक्षण, वृक्षारोपण,

आजीविका वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा मिली।

गौतम कुमार सिंह का दृष्टिकोण 'समग्र, वैज्ञानिक और मानव-केंद्रित' है। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि जब प्रशासनिक नेतृत्व, तकनीकी ज्ञान और सामुदायिक भागीदारी एक साथ आते हैं, तो 'जन शक्ति से जल शक्ति' का सपना साकार किया जा सकता है।



विनोद खाती

हेस्को, देहरादून, उत्तराखंड

पहाड़ों पर जब चली नदी तो खेती, पहाड़ी, जमीन मुस्कुराई, वैज्ञानिक पद्धति से खुशहाली छाई



उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में 170 से अधिक प्राकृतिक स्रोत व 7 छोटी नदी-धाराएं पुनर्जीवित हुई हैं। कम वर्षा वाले वर्षों में भी स्रोतों के प्रवाह बढ़ा है।

हिमालयन एनवायरनमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गनाइजेशन (हेस्को), देहरादून के विनोद खाती ने हिमालयी क्षेत्र में सूखते स्रोतों और छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने में उर्जा लगाई; पद्म भूषण, पद्मश्री डॉ. अनिल प्रकाश जोशी के मार्गदर्शन में विनोद खाती ने यह दिखाया है कि वैज्ञानिक नवाचार और सामुदायिक सहभागिता के संयोजन से पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की जीवनरेखा बने जलस्रोतों को कैसे पुनर्स्थापित किया जा सकता है।

माउंटनेस स्प्रिंग्स एंड रिवर रीचार्जिंग परियोजना, एक्सप्लोरिंग हाइड्रोजियो केमिकल टेक्निक्स इन द हिमालयाज आज हिमालयी जल संरक्षण और पारिस्थितिक-हाइड्रोलॉजिकल पुनर्स्थापन का एक अग्रणी मॉडल बन चुका है। इस पहल का एक प्रमुख वैज्ञानिक आधार रहा 'आइसोटोप हाइड्रोलॉजी' का उपयोग, जो 'भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर, मुंबई' के सहयोग से संभव हुआ। टीम द्वारा स्रोतों, धाराओं और रीचार्ज क्षेत्रों से किए गए जल-नमूना विश्लेषण ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आइसोटोपिक संकेतों के माध्यम से रीचार्ज ऊँचाइयों, भूमिगत प्रवाह मार्गों और जल के भूगर्भीय मूल की सटीक पहचान सुनिश्चित की। इस वैज्ञानिक समझ ने विभिन्न भू-



आकृतिक स्थितियों के अनुसार लक्षित और सटीक रीचार्ज संरचनाओं के निर्माण को संभव बनाया।

इन वैज्ञानिक निष्कर्षों के आधार पर 'कंटूर ट्रेच', 'चेक बंड', 'गैबियन बांध', 'परकुलेशन तालाब', और 'इन्फिल्ट्रेशन ट्रेच' जैसी कई कृत्रिम जलसंचयन संरचनाएं बपसई गईं। इन प्रयासों से भूजल पुनर्भरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, सतही बहाव कम हुआ और कमजोर पर्वतीय ढलानों को स्थिरता प्राप्त हुई। इसके साथ ही, ओक, भिमल, बुरांश और साइटस जैसी स्थानीय प्रजातियों का व्यापक रोपण किया गया, जिससे मिट्टी की संरचना सुधरी, जल अवशोषण बढ़ा और क्षतिग्रस्त जलग्रहण क्षेत्रों की पारिस्थितिकी पुनर्जीवित हुई।

इस पूरी पहल का केंद्र 'सामुदायिक भागीदारी' रहा। ग्रामीणों को रीचार्ज जोन

पहचानने, जलस्रोतों के कैचमेंट क्षेत्रों की रक्षा करने, रीचार्ज संरचनाओं का रखरखाव करने तथा मौसमी जल-प्रवाह की निगरानी करने का प्रशिक्षण दिया गया। सामुदायिक स्वामित्व की यह भावना परियोजना को एक तकनीकी हस्तक्षेप से आगे बढ़ाकर एक 'जन-आधारित संरक्षण आंदोलन' में बदलने में निर्णायक सिद्ध हुई। परियोजना का प्रभाव अत्यंत उल्लेखनीय है। 'उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में 170 से अधिक प्राकृतिक स्रोत और सात छोटी नदी-धाराएं पुनर्जीवित' हुई हैं। कम वर्षा वाले वर्षों में भी स्रोतों के प्रवाह में '25 से 243 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जल उपलब्धता में सुधार से कृषि उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, गेहूँ की पैदावार 70 से बढ़कर 125 किलोग्राम प्रति नाली और धान की पैदावार 50 से बढ़कर 105 किलोग्राम प्रति नाली हो गई। बेहतर जल उपलब्धता ने सब्जी उत्पादन, मत्स्य पालन और पशुपालन को भी प्रोत्साहित किया, जिससे ग्रामीण आय में वृद्धि हुई और महिलाओं का जल-संग्रह का बोझ कम हुआ।

इस पहल ने मिट्टी की नमी बढ़ाई, ढलानों को स्थिर किया और स्थानीय जैव-विविधता को पुनर्जीवित किया। सामाजिक स्तर पर, इसने

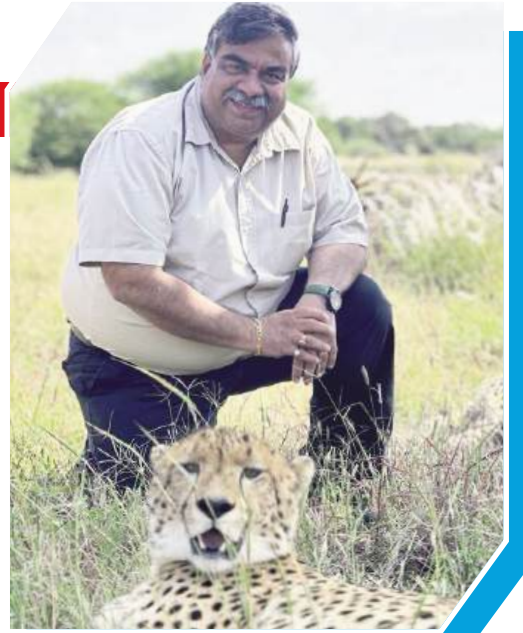
समुदायों को अपने प्राकृतिक संसाधनों के दीर्घकालिक संरक्षक के रूप में सशक्त बनाया। वैज्ञानिक स्तर पर, इसने यह सिद्ध किया कि हिमालय जैसे जटिल पर्वतीय क्षेत्रों के जल-संकट के समाधान में 'आइसोटोप हाइड्रोलॉजी' कितनी प्रभावी हो सकती है। यह योगदान हिमालयी क्षेत्र में जलवायु-लचीलापन और सतत विकास का एक प्रेरणादायक प्रकाश स्तंभ है।



डॉ. बृजकिशोर गुप्ता

निदेशक, ग्रीन्स जूलाँजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, वनतारा

जल संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण हैं एक-दूसरे के पूरक हैं, प्राकृतिक दुनिया में कृत्रिम जल स्रोतों वंतारा तस्वीर



वंतारा जैसी आदर्श पहलों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे अन्य संस्थाओं को भी प्रेरणा मिले कि वे अपने परिसरों, परिचालनों और समुदायों में मजबूत जल-प्रथाओं को अपनाएं।

जल संरक्षण, संवर्धन राष्ट्रीय अभियान में एक अग्रणी संस्था के रूप में जामनगर स्थित '3500 एकड़ में फैला वंतारा द ग्रीन्स जूलाँजिकल, रेस्क्यू एवं रिहैबिलिटेशन सेंटर' दृढ़ संकल्प और स्पष्ट दृष्टि के साथ उभरकर सामने आया है। वन्यजीव बचाव और संरक्षण के प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र के रूप में अपनी भूमिका से आगे बढ़कर, वंतारा आज 'सतत संसाधन प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, और पारिस्थितिक पुनर्स्थापना' का प्रेरक उदाहरण बन चुका है।

इस विशाल प्राकृतिक अभयारण्य में जल मात्र एक सुविधा नहीं, बल्कि हर जीव का जीवन-धर्म माना जाता है। वंतारा के तालाब, वेटलैंड और कृत्रिम झीलें 'जल अर्थव्यवस्था' के आदर्श मॉडल हैं। प्राकृतिक कैचमेंट क्षेत्रों को पुनर्जीवित कर मानसूनी जल संग्रहित किया गया है। भूमि की बनावट इस प्रकार विकसित की गई है कि जल फिल्ट्रेशन बेड और रिचार्ज शाफ्टों की श्रृंखला से होते हुए भूमिगत जलस्तर को समृद्ध करता है।

यह संरक्षण केवल एक नारा नहीं, बल्कि जीवन पद्धति है, जहां 'विज्ञान और आस्था साथ-साथ चलते हैं'। 'जल आत्मनिर्भर भारत 2047' के संकल्प को ऐसे ही प्रयास नई शक्ति प्रदान



करते हैं। वंतारा जैसे स्थानों में यह राष्ट्रीय आकांक्षा आकार लेती है, जहां हर बूंद का सम्मान किया जाता है और हर प्रयास सह-अस्तित्व की भावना का विस्तार है।

पांच सफल संस्करण में जल प्रहरी सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित जल-संरक्षण सम्मानों में से एक बन चुका है। 'जल शक्ति मंत्रालय, नीति आयोग, नमामि गंगे, नेशनल वाटर मिशन और जल जीवन मिशन' के सहयोग से आयोजित यह सम्मान उन प्रशासकों, वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों,

और सामुदायिक नेताओं को गौरवान्वित करता है जिन्होंने भारत की जल-परिदृश्य यात्रा को बदल दिया है। वंतारा की पहलें भी इसी राष्ट्रीय कथा का गौरवपूर्ण हिस्सा हैं।

केंद्र की एकीकृत जल प्रबंधन प्रणाली दशार्ती है कि पशु-कल्याण हेतु स्थापित संस्था कैसे 'जलवायु-लचीलापन का जीवंत रूप बन सकती है। पशु परिसरों से बहने वाले जल का उपचार कर उसे उद्यानिकी में पुनः उपयोग किया जाता है, अपशिष्ट जल को प्राकृतिक रीड-बेड प्रणालियों से शुद्ध किया जाता है और विशाल वृक्ष-आवरण वाष्पीकरण को न्यूनतम कर भू-जल पुनर्भरण को अधिकतम करता है।

मूलतः, वंतारा की पारिस्थितिकी उसके मूल चिंतन को प्रतिबिंबित करती है, 'हर जीवन का सम्मान, और जल का जिम्मेदार उपयोग'। जलवायु अनिश्चितताओं के दौर में वंतारा एक 'संतुलन और समन्वय का मार्गदर्शक' है। जहाँ प्राकृतिक प्रणालियां पुनर्जीवित होती हैं और मानव संकल्प क्षरण नहीं, बल्कि पुनर्स्थापन चुनता है। उसका संकल्प यह दशार्ती है कि 'हर जीवन की रक्षा एक बूंद बचाने के समान है', और वास्तविक प्रगति विस्तार में नहीं, बल्कि संतुलन में निहित है।



पद्मभूषण अनिल प्रकाश जोशी

हेस्को, उत्तराखण्ड

हिमालय की आवश्यकता लोगों से ही नहीं जुड़ी, बल्कि ज्यादा बड़ा योगदान देश के प्रति



गंभीरता इस रूप में भी समझ लेनी चाहिए कि अब हिमालय जिस तरह से बाढ़, जलवायु परिवर्तन और तपती धरती को झेल रहा है, इन परिस्थितियों पर नए तरीके से नीतियों के बारे में सोचना होगा खास तौर से ढांचागत विकास, बनावट की नीति व हवा, मिट्टी, जंगल, पानी के संरक्षण के नए आयाम।

हिमालय में हो रही घटनाओं पर अब एक नए सिरे से सोचना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिमालय मात्र हिमालय के लोगों से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि इसका ज्यादा बड़ा योगदान देश के प्रति है। अगर यह कल्पना कर ली जाए कि हिमालय न हो, तो लगभग दो अरब लोग भोजन और पानी से वंचित हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, हिमालय के उपकार अनगिनत हैं।

इतिहास इसका साक्षी है कि हिमालय ने देश की रक्षा के अलावा देश को हवा, मिट्टी और पानी के रूप में अविश्वरूप सेवा दी है। इसने खुद जख्म झेले हैं, लेकिन लोगों के संकटों को दूर किया है। देश को ही देख लीजिए – ब्रह्मपुत्र, गंगा और यमुना जैसी बड़ी नदियाँ देश को सींचती हैं और तमाम तरह की आर्थिक क्रांति के आधार हैं।

आज अगर हिमालय व्यथित है, तो यह हिमालय से ज्यादा उनका दायित्व हो जाता है जो हिमालय को ज्यादा भोगते हैं। स्पष्ट है कि यह देश की बात है। राज्य का दर्जा मिलने भर से हिमालय के प्रति अपने दायित्व से केंद्र मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि एक बार यदि यह भी सोच लिया जाए कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था हिमालय के प्रति कर दी गई है, लेकिन हिमालय के उपकार पूरे देश



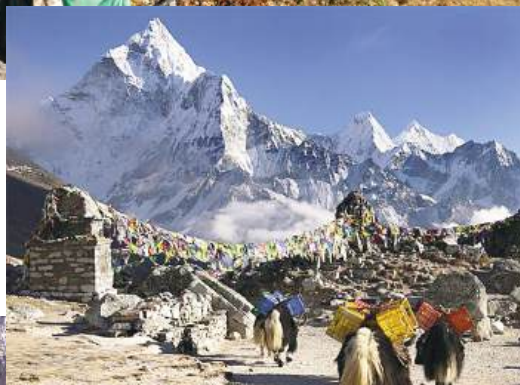
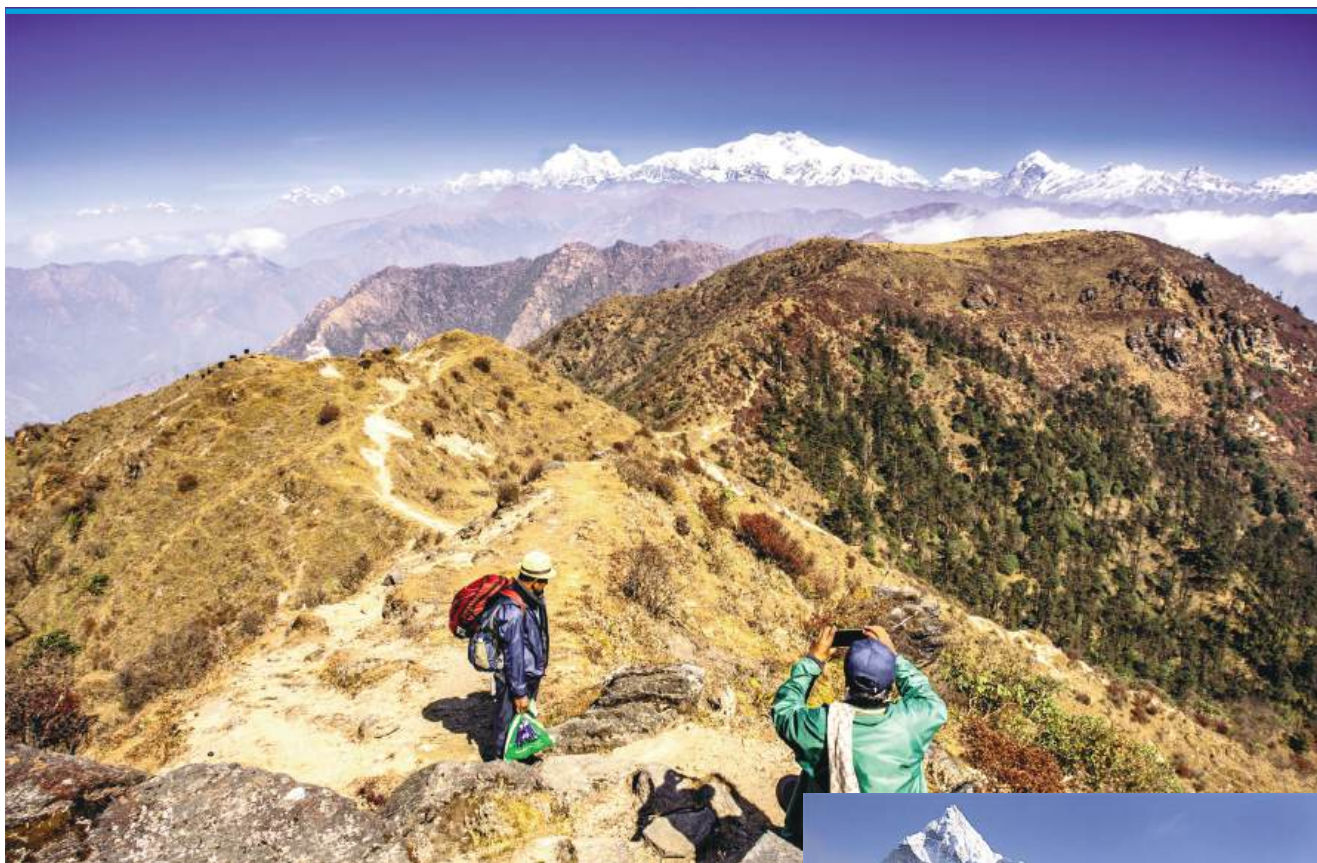
में हैं और देश की कई आर्थिक गतिविधियाँ हिमालय से जुड़ी हुई हैं।

अगर आज जो कुछ भी हिमालय में हो रहा है वह घटता चला गया, तो इसका बड़ा असर उन पाँच करोड़ लोगों से ज्यादा सत्तर करोड़ लोगों पर होगा जो किसी न किसी रूप में हिमालय को भोगते हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि केंद्र को हिमालय के प्रति अब गंभीरता से सोचना होगा।

प्रधानमंत्री हिमालय के प्रति बड़े संवेदनशील हैं। उत्तराखंड उनके लिए एक दूसरे घर की तरह समझा जा सकता है। और वही इसकी संवेदनशीलता को समझते हुए अगर कोई कदम उठाएँ, तो शायद हिमालय के बचने-बचाने की बात पर गंभीरता भी आ ही जाएगी।

गंभीरता इस रूप में भी समझ लेनी चाहिए कि अब हिमालय जिस तरह से बाढ़, जलवायु

परिवर्तन और तपती धरती को झेल रहा है, इन परिस्थितियों पर नए तरीके से नीतियों के बारे में सोचना होगा – खास तौर से ढांचागत विकास, बनावट की नीति और हवा, मिट्टी, जंगल, पानी के संरक्षण के नए आयाम। यह सब अगर कहीं भी रोजगार मान लिए जाएँ, तो हिमालय के लोगों के पास इस रूप में रोजगार का मतलब देश की सेवा भी होगी और वे कार्य भी पर्यावरण को – जो कि हिमालय की पारिस्थितिकी को एक समृद्धि प्रदान करेंगे आगे बढ़ाएँगे। जब दुनिया में उत्पादक उद्योग संभव है तो पारिस्थितिकी उद्योग क्यों नहीं हो सकता। आज जनजाति और वनवासियों का पारिस्थितिक उद्योग ही उनके अनुरूप है। शहर उत्पादों के उद्योग और गांव पारिस्थितिकी के उद्योग होंगे तब ही हम इकॉनमी तथा इकोलॉजी दोनों के बीच संतुलन भी साध पाएँगे साथ में शहर और गांवों के आर्थिक सामाजिक समानता में भी सीधा असर पड़ेगा। यह सब विषय हैं जिन पर गंभीरता की आवश्यकता है, और यह एक बड़ा रूप तभी ले सकेगा जब देश का नेतृत्व इस पीढ़ा को समझते हुए हिमालय और उसके लोगों की ओर तथा देश में होने वाले संकटों में स्वयं आगे बढ़कर निर्णय ले।



छोटी नदियों को पुनर्जीवित करना सबसे पहली जरूरत है



राजेन्द्र सिंह

भारत के भूजल भंडार खाली होने से हमारी सारी छोटी नदियां सूख कर मर रही हैं। इसलिए छोटी नदियों को पुनर्जीवित करना सबसे पहला काम होना चाहिए। वेदों के अनुसार 14.6 किलोमीटर लंबाई वाली जलधारा को नदी कहा जा सकता है। आधुनिक में नदी की परिभाषा, विन्यास और स्वरूप के नाप में परिवर्तन आया है। पर भारतीय शास्त्रों में जिसे नदी कह सकते हैं, वह 14.6 किलोमीटर लंबी होना जरूरी है। इतनी या उससे अधिक लंबाई वाली जलधारा को भी भारत में नदी कहा जा सकता था।

यू तो भारत की नदियां की लंबाई 2800 किलोमीटर तक है, परंतु इस 2800 किलोमीटर लंबी नदी में सैकड़ों और हजारों छोटी नदियां बन जाती हैं। इन छोटी नदियों को जब तक हम शुद्ध सदानिरी बनाकर, पुनर्जीवित नहीं करेंगे, तब तक

भारत को पानीदार बने रहने में शंका है। भारत को यदि पानीदार बनना है तो छोटी नदियों को शुद्ध सदानिरी बनाने के लिए धरती का पेट पानी से भरना होगा। जब हम धरती का पेट पानी से भरेंगे, तब हमारी नदियां शुद्ध सदानिरी होकर बहने लगेंगी।

आज नदियों का सतही प्रवाह, अधो भूजल और भूजल प्रवाह के साथ गहरा योग रखता है। इस योग को देखना और समझना बहुत जरूरी है। तरुण भारत संघ ने सबसे पहले अरवरी को पुनर्जीवित करने का काम किया था। इस नदी को पुनर्जीवित करने में 12 साल लगे थे। लेकिन इस नदी की लंबाई भी 60 किलोमीटर है। इस 60 किलोमीटर लंबी नदी में बहुत सारी छोटी धारा है जो 14.6 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है; उन्हें नदी बोला जा सकता है। पर वहां का समाज केवल इसकी जो मुख्य धारा को ही ह्रारवरी नदी बोलते हैं। तरुण भारत संघ ने यह तनिक भी प्रयास नहीं किया कि, उसकी अलग धाराओं को

कुछ नए नाम देकर नदी बोलें। क्योंकि ज्ञान, लोक विज्ञान और लोक समझदारी में नाम के निर्धारण है, उन्हीं को मानना और उन्हीं के अनुरूप आगे चलकर, काम करना ही अच्छा होता है। इसलिए तरुण भारत संघ ने उन्हें प्राचीन लोगों के दिए हुए नाम का पालन किया, उन्हीं को अपनाया है।

इसी तरह यमुना में कई सहायक, उपसहायक अलग-अलग नदियों को नदी मानना जरूरी है। आजकल भारत सरकार और राज्य सरकारें नदियों के पुनर्जीवन के लिए बहुत बातें कर रही हैं। नदी पुनर्जीवन का भारत सरकार ने एक अलग से मंत्रालय भी बनाया, लेकिन नदियां तो मंत्रालय बनने के बाद भी तेजी से सूख ही रही हैं। नदियां गंदे नाले बन रहे हैं और बेपानी होकर मर रही हैं। यह नदियों का मरना यह बताता है कि, जब किसी देश की नदियां सूखने लगती हैं, तो वहां की सभ्यताएं भी सूखकर मर जाती हैं। भारत एक सांस्कृतिक समृद्ध सभ्यता का धनी है। इस भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक समृद्ध राष्ट्र की



नदियां यदि सूख रही हैं, फिर हम कैसे कहें कि, हमारी सभ्यता और संस्कृति समृद्ध है? सभ्यता और संस्कृति को जन्म देने वाली नदियां सूख गई हैं। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण करने के लिए, अपनी सभ्यताओं को नदियों के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है।

नदियों के पुनर्जीवन और भूजल के पुनर्भरण इन दोनों का गहरा रिश्ता है। भारत सरकार को अटल भूजल योजना और नदी पुनर्जीवन इन सबको एक साथ जोड़कर, एक बड़े अभियान के तौर पर काम शुरू करना चाहिए। यदि सरकार की भूजलपुनर्भरण का काम तेज नहीं करेगी, तो भारत की छोटी नदियां सूखती ही जाएंगी। साल में कभी भी एक महीना या दो महीना वर्षा देरी से होगी तो सब बेपानी होने लगेंगे। इसलिए भूजल के भंडारों को भरना होगा।

भारत में जब तक जल का संरक्षण करके, भूजल पुनर्भरण नहीं होगा, तब तक भारत समझदार, इज्जतदार और पानीदार नहीं बन सकता। भारत को वर्षा जल की एक-एक बूंद का संग्रह करके, भूजल में सुरक्षित रखना होगा। ऐसे काल में उस वर्षा जल से पुनर्भरण होने वाले जल को हम संरक्षित और सुरक्षित करके, अनुशासित होकर उपयोग करने के काम में लगे। तब भारत की बेपानी धरती व नदियां पानीदार बन जाएगी। इस हेतु नदियों के पर छोटे-छोटे काम भी बहुत

नदी पुनर्जीवन का भारत सरकार ने एक अलग से मंत्रालय भी बनाया, लेकिन नदियां तो मंत्रालय बनने के बाद भी तेजी से सूख ही रही हैं। नदियां गंदे नाले बन रहे हैं और बेपानी होकर मर रही हैं। यह नदियों का मरना यह बताता है कि, जब किसी देश की नदियां सूखने लगती हैं।

प्रभावित परिवर्तन कर सकते हैं।

छोटी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में जितने भी जलधाराएं हैं, उनको उद्गम से लेकर संगम तक रक्षण-संरक्षण किनारों पर रहने वाले समाज के द्वारा करना जरूरी है। उस जल संरक्षण से ही वहां का भूजल पुनर्भरण होगा। भूजल पुनर्भरण से सूखी छोटे-छोटे झरने व जलधाराएं फिर से बहने लगेंगी। इस समय हमें छोटी जलधाराओं को बहने योग्य शुद्ध सदानीरा होकर, धरती को हरा-भरा बनाकर, धरती पर रहने वाले लोगों को नदियों के साथ जुड़ना होगा।

भारत छोटी नदियों को पुनर्जीवित करेगा, तो भारत का समाज नदियों के साथ जुड़कर, नदियों को शुद्ध सदानीरा बनाने में जुट जाएगा। इसकी

शुरूआत सरकारों को करनी होगी क्योंकि समाज जब भी कोई नदी पर काम करता है, तो सरकार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर देती है। इसलिए लोग नदी पर काम करने से डरते हैं। सरकारी यदि आगे आकर इस तरह के काम करेगी तो मेरी समझ में एक सुखद बदलाव होगा। जैसे महाराष्ट्र में 'जल साक्षरता और चला जानूया नदीला' कार्यक्रम आरंभ होने से प्रदेश के युवा नदियों के साथ जुड़ गए और युवा लोगों ने अपने नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए नदियों के संकट समाधान करने में लगे हैं। इससे छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने बड़ा सहयोग हो रहा है। जब समाज एक साथ मिलकर ऐसे कार्य करे तो नदियां भी पुनर्जीवित हो जाती हैं।

Lovibond® AquaRover™ – India's Water Quality Revolution on Wheels

Because safe water shouldn't depend on distance. It should depend on accuracy.



Across India, millions rely on water that travels miles before it reaches them. But how often does testing travel to them?

Introducing Lovibond® AquaRover™, the first-of-its-kind, solar-powered Mobile Water Testing Laboratory that brings science, accuracy, and trust directly to the community.

Whether it is a bustling town, a remote hamlet, a construction site, a riverbank, or an industrial zone—AquaRover™ takes the lab to the problem, not the other way around.

A Lab Built for the Field. A Mission Built for India.



✓ Complete Testing on Site

Conduct all major physical, chemical, and bacteriological tests for drinking water, wastewater, groundwater, aquaculture, and environmental monitoring—all from inside the AquaRover™.

✓ 100% German Precision Instruments

Powered by Lovibond® photometers, spectrophotometers, turbidimeters, microbiological incubators, samplers and more—delivering traceable, reliable, compliance-ready results every time.

✓ Solar-Powered Sustainability

Motorised solar panels generate up to 3.48 kW, allowing uninterrupted testing even in non-electrified areas. Because clean water should not cost the planet.

✓ Designed for Tough Terrains

Shock-proof interiors, rugged fabrication, and CIRT/ARAI-approved build make AquaRover™ ready for:

- Remote areas
- District monitoring
- Flood/contamination Emergencies
- On-site inspections
- CSR & awareness drives

✓ Smart Digital Integration

Instant data logging, reporting & record-keeping — no errors, no delays.



From Awareness to Action — AquaRover™ Does It All

Not just testing. AquaRover™ supports:

- Water quality awareness drives
- Sample collection campaigns
- Departmental demonstrations
- Government flagship missions
- Quick response during outbreaks or contamination
- Large-scale monitoring (JJM, Smart Cities, Water Boards)
- Environmental & NGO initiatives

Wherever water needs attention, AquaRover™ becomes the centre of action.

A Mobile Lab with Heart and Intelligence

A space designed for scientists

Smart workspace, DI water system, AC, safety systems, organised storage.

A tool built for administrators

FFast reporting, reduced lab dependency, cost-efficient operations.

A hope built for communities

Clear, accessible water information — when it matters most.

AquaRover™ makes water quality visible, understandable, and accessible to everyone.

Why India Chooses AquaRover™

- 140+ Years of Water Testing Expertise
- Proprietary Lovibond® Reagents
- Trusted in 160+ Countries
- Complies with BIS, ISO, WHO Standards
- Pan-India Service & Support
- Customisable layouts and equipment
- FDSS for lab safety



When accuracy matters, trust the name that has built water testing for over a century—Lovibond®.

AquaRover™ – Water Quality. Anywhere. Anytime.
From field to facts... in just minutes.

■ Tintometer India Private Limited, Hyderabad ☎ 1800 599 3891/3892 ■ indiaoffice@lovibond.in 🌐 www.lovibond.in

HURL



MAKING INDIA SELF-RELIANT IN UREA PRODUCTION

BUSINESS TERRITORY

BIHAR
ASSAM
ODISHA
PUNJAB
HARYANA
RAJASTHAN
JHARKHAND
WEST BENGAL
MAHARASHTRA
CHHATTISGARH
UTTAR PRADESH
MADHYA PRADESH

Hindustan Urvarak & Rasayan Limited (HURL)

is a pioneering force in India's agricultural landscape, dedicated to empowering farmers and enhancing agricultural productivity. As a prominent joint venture of Maharathna CPSEs – Coal India Limited, National Thermal Power Corporation Limited, Indian Oil Corporation Limited and of other two companies i.e. Fertilizer Corporation of India Limited & Hindustan Fertilizer Corporation Limited, HURL is committed to produce high-quality urea through its state-of-the-art manufacturing facilities located in Gorakhpur, Barauni and Sindri.

Our mission extends beyond production; about promoting sustainable farming practices. With innovative products, we enable farmers to improve crop yields and enrich soil health, paving the way for a greener and prosperous future.

At HURL, we believe in collaboration and are driven by a vision of transforming India's agricultural ecosystem. Join us on this journey toward sustainable agriculture and empowered farming communities!

PRODUCTION UNITS

📍 GORAKHPUR (U.P.)
📍 BARAUNI (BH)
📍 SINDRI (JH)



॥ हर एक काम, देश के नाम ॥

HINDUSTAN URVARAK & RASAYAN LTD

(A Joint Venture of CIL, NTPC, IOCL, FCIL & HFCL)

Core-4, 9th Floor, SCOPE Minar, Laxmi Nagar District Centre, Delhi-110092

www.hurl.net.in | www.hurl | [hurl_india](https://in.linkedin.com/company/hurl-india) | [hurl-india](https://www.facebook.com/hurl-india) | [@hurl-india](https://twitter.com/hurl-india)

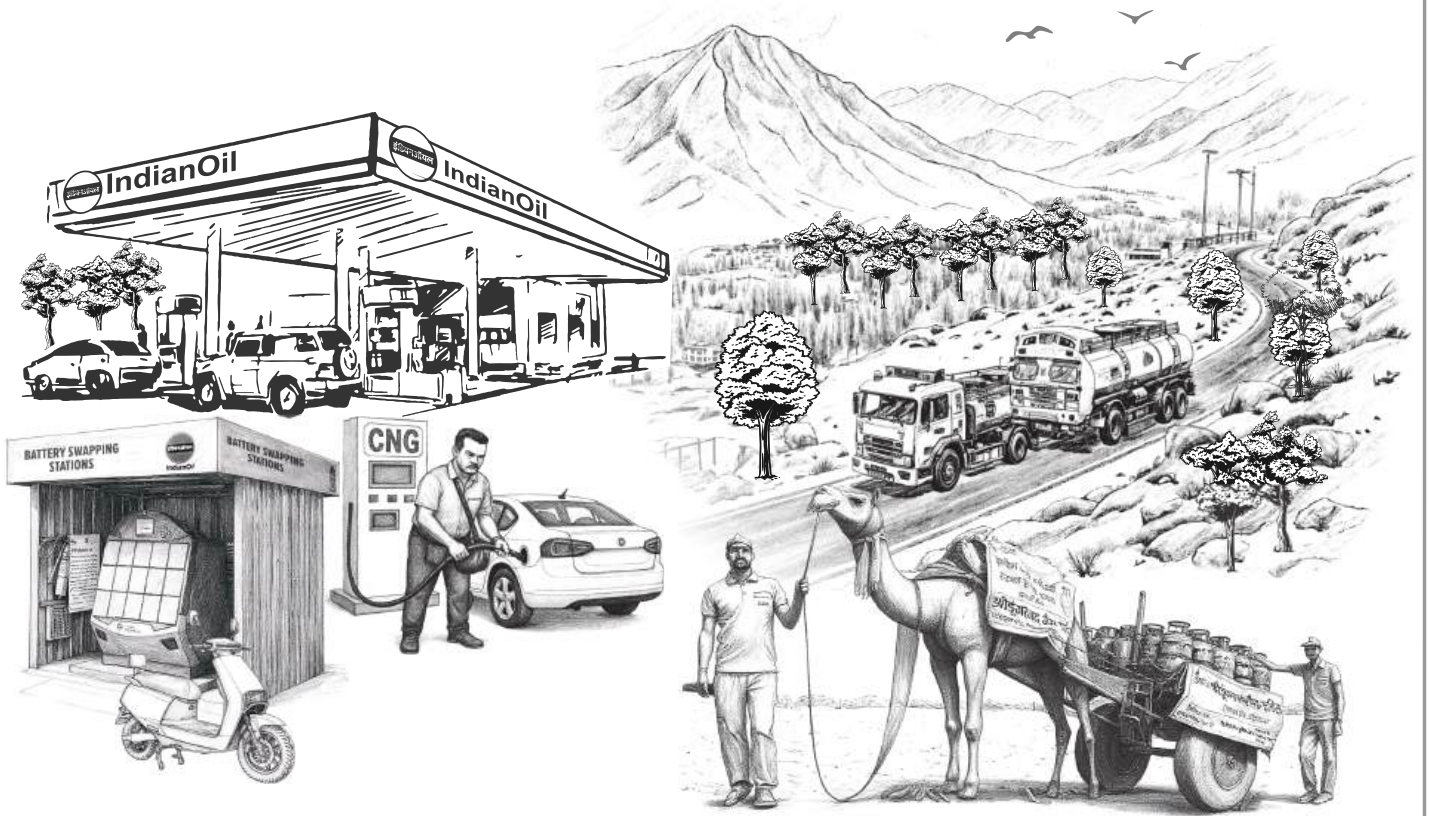


IndianOil



इंडियनऑयल

हर पल, हर कदम जीवन और विकास के संग



- पूरे देश में इंडियनऑयल के 63,000 से ज़्यादा ग्राहक सेवा केंद्र हैं।
- सुबह की चाय से लेकर रात के भोजन तक – 15 करोड़ रसोई घर इंडेन गैस से चलते हैं।
- 'सर्वो' भारत का सबसे पसंदीदा लुब्रिकेंट है, जिस पर 45 देशों के लोग भरोसा करते हैं।
- 130 विमानन ईंधन स्टेशनों के साथ भारत में हवाई उड़ानों को ऊर्जा देने में इंडियनऑयल सबसे आगे है।
- Grease Miracle, STORM-X जैसे नवीन उत्पादों से व्यापारिक गतिवर्धन से इंडियनऑयल इस क्षेत्र को नई दिशा देता है।

